



लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 पेश

विपक्ष के लगातार विरोध और शोर-शराबे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी

नई दिल्ली/एजेंसी

विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026" पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। विपक्ष के लगातार विरोध और शोर-शराबे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी समय तक स्थगित रही। सुबह 11 बजे दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार हंगामे के कारण पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी गतिरोध बना रहा, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने वर्ष 2024 में बने कानून में संशोधन के लिए यह विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के आरोपितों के लिए अधिक कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित



प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई को कानून को और सख्त बनाने की घोषणा की थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जुलाई को कानून को और सख्त बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की भी घोषणा की गई। इस बीच पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों ने उनका शॉल

करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, जहां ऐसे मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी। यह कानून केंद्र सरकार और उसकी



प्रदर्शनकारी युवाओं को डराया जा रहा: खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं को धमकाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में और मिथिला पाग पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें संसद भवन के भीतर तक लेकर गए। इस दौरान

कई युवाओं को जबरन हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब प्रदर्शन में शामिल युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंटों की भी जांच-पड़ताल की जा रही है, जो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। सांसदों ने 'धर्मेन्द्र प्रधान जिंदाबाद' के नारे भी लगाए। नीट पेपर लीक विवाद के बीच धर्मेन्द्र प्रधान ने 25

जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उल्लेखनीय है कि तीन मई, 2026 को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करनी पड़ी थी। इस मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एजेंसी जल्द ही आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।

का कहना है कि यह संशोधन नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के मद्देनजर लाया गया है।

'पेपर लीक बिल' पर चर्चा न होने देना दुर्भाग्यपूर्ण: रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि देशभर के छात्रों की मांगों और हाल में हुए छात्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यदि इतने बड़े छात्र आंदोलन के बाद भी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो पाती, तो यह न संसद के लिए अच्छा है और न ही लोकतंत्र के लिए। संसद बहस और चर्चा का सर्वोच्च मंच है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहीं सार्थक चर्चा होनी चाहिए। रिजिजू ने संसद भवन परिसर में प्रचारकों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

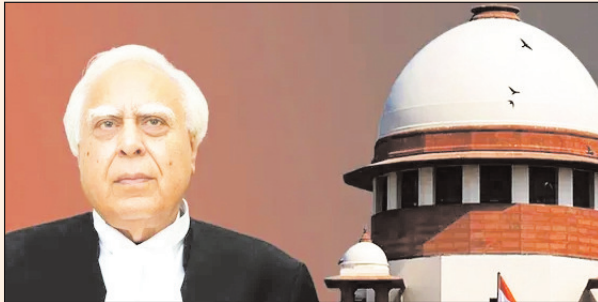


हंगामे के कारण राज्यसभा में नहीं हो सकी वंदेमातरम से जुड़े विधेयक पर चर्चा

नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को भी व्यवधान जारी रहा और इसके चलते राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने विधेयक पर चर्चा कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। पहले सुबह ग्यारह बजे कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक फिर दो बजे तक और फिर शाम

5.15 मिनट तक स्थगित कर दिया गया। शाम को भी हंगामा नहीं थमा। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद के बाहर बोलने का अवसर नहीं मिलने की शिकायत करती है, जबकि सदन के भीतर चर्चा होने नहीं दे रही है। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से निर्धारित एजेंडे के अनुसार चर्चा आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

कपिल सिब्बल ने दल-बदल विरोधी कानून को दी चुनौती



नई दिल्ली/एजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती देने वाली कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल इस अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता अपनाकर विधायक दलबदल कानून के तहत अयोग्यता से बच जाते हैं। बता दें इस याचिका को वरिष्ठ वकील सिब्बल ने खुद पक्षकार बनकर दायर किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सिब्बल की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में उठाए गए कई मुद्दों पर संसद को विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। सिब्बल ने दलील दी है कि इस मुद्दे का हमारी राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया, 'इस व्याख्या के कारण कोई अल्पसंख्यक पार्टी बहुमत वाली पार्टी बन सकती है

या बहुमत वाली पार्टी अल्पसंख्यक बन सकती है।' बेंच ने कहा कि दसवीं अनुसूची, जो विधायकों के दल-बदल को कंट्रोल करती है, संसद द्वारा बनाई गई थी और इसके लिए सही तरीका तय करना विधायिका का काम है। सिब्बल ने कोर्ट को यह भी बताया कि गोवा में विधायकों के दल-बदल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद बेंच ने सिब्बल की याचिका को गोवा वाले मामले के साथ जोड़ दिया। याचिका में इस बात पर स्पष्टता मांगी गई है कि क्या मौजूदा व्याख्या के तहत विलय के प्रावधान से संसद और राज्य विधानसभाओं के गठन में बदलाव की अनुमति है, बिना इसके कि एंटी-डिफेक्शन कानून (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता लागू हो। सिब्बल ने 22 जुलाई को अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला इस बात से जुड़ा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: नई एसआईटी गठित, सीए भी होगा सदस्य

नई दिल्ली/एजेंसी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्य बागची और वी. मोहना की बेंच की सामने यूपी सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच के लिए एसआईटी का दोबारा गठन किया गया है।

SC में UP सरकार ने रखा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों को अपनाते हुए नई गठित एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल



किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को जांच विभाग का प्रमुख बनाया गया है। साथ ही तीन सदस्यीय एसआईटी में दो सीनियर IPS अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें

अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक सोमेन बर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव गौवर शामिल हैं। इस नई गठित एसआईटी पर सुप्रीमकोर्ट ने सुझाव दिया कि टीम में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए।

पांचवें सदस्य के तौर पर फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जल्द ही **CA** को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह एसआईटी में पांचवें सदस्य के तौर पर एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे। यह टीम दो हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची और वी। मोहना की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों



पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए रकब का गठन किया गया था।

बेंच ने क्या कहा?

बेंच ने सुनवाई को दो हफ्ते के लिए टालते हुए कहा, 'पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हम घटना की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं।' 'हम निष्पक्ष, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच कराने पर ध्यान दे रहे हैं।' 20 जुलाई को बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह दान के कथित गबन की जांच के लिए एसआईटी बनाने की संभावना के बारे में जानकारी दे।

नीट पेपर लीक: फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली

नई दिल्ली/एजेंसी

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टल गई। सुनवाई टलने की वजह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से लोक अभियोजक की अभी तक नियुक्ति नहीं की है। रस्ट ट्रैक कोर्ट की नवनिर्गुप्त जज अनु ग्रावर बलिंग ने इस मामले के आरोपितों विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य



न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था। जज अनु ग्रावर बलिंग को नियुक्त किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट सार्वजनिक परीक्षा

में हो रहे अपराध से जुड़े मामलों सुनवाई करेगी। ये कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन्स) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगी।

आईएस केशव चंद्र ने संभाला खान सचिव का पदभार

नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ अधिकारी केशव चंद्र ने सोमवार को भारत सरकार के खान सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। खान मंत्रालय ने उनके कार्यभार संभालने की जानकारी आधिकारिक बयान के माध्यम से दी। 1995 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी मंत्रालय के अनुसार, केशव चंद्र अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एंव केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1995 बैच के आईएसएस अधिकारी हैं। उन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है।

असम में बाढ़ से नौ जिलों की 524733 आबादी प्रभावित

गुवाहाटी/एजेंसी

असम में बाढ़ का पानी अब तेजी से उतरने लगा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, वहीं घरों, सड़क, विद्यालयों में पानी के साथ आई मिट्टी की गाद से एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। प्रभावित नागरिकों की आंखों में एक शून्यता देखने को मिल रही है। सरकार हर संभव कदम उठाने का लगातार दावा कर रही है, बावजूद हालात ने एक नई चुनौती उत्पन्न कर दी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के 26 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में दो और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह राज्य में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 68 हो गई है। असम में धनसिरी (नुमालीगढ़) नदी खतरे के



निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार रात सोशल मीडिया के जरिए बताया कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद राज्य के सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में

जाकर स्थिति का आकलन करेंगे। बाढ़ से वर्तमान में कुल नौ जिले अभी भी बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिसमें चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, होजाई, कामरूप, नगांव, कामरूप (मेट्रो)

एवं डिब्रूगढ़ जिला शामिल हैं। बाढ़ से नौ जिलों के 24 राजस्व मंडलों के कुल 763 गांव प्रभावित हैं। राज्य की कुल 524733 आबादी एवं 48742.09 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कुल 109 राहत शिविर एवं 345 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 245 शिविर स्थापित किए हैं। राहत शिविरों में 37724 लोग आश्रय लिए हुए हैं। राहत वितरण केंद्रों पर 153833 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से 26 जुलाई को भी चराईदेव जिले में दो शव बरामद हुए। बाढ़ से प्रभावित जानवरों की कुल संख्या 88240 दर्ज हुई है, जिसमें बड़े 45895, छोटे 26335 एवं मुर्गी-पालन 16010 दर्ज हुए हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में कुल 26512 जानवर बह गए।



संपादकीय

संकट बनती निमार्णाधीन सुरंगें

मानव जीवन के लिए प्रकृति को छलनी कर किया जा रहा आधुनिक विकास, जहां जरूरी है, वहीं संकट का सबब भी बन रहा है। सिक्किम के नामची जिले में समरडुंग-झोलुंग में नामची जल विद्युत सुरंग परियोजना (तीस्ता नदी चरण-5) की निमार्णाधीन सुरंग में तेज बारिश, भूस्खलन और जहरीली गैस मीथेन के रिसाव चलते बड़ी दुर्घटना घटी है। इसमें 20 मजदूरों की मौत हो गई। कुल 25 मजदूर घटना के समय सुरंग में काम कर रहे थे। 500 मेगावाट की इस परियोजना में विस्फोट के कारण मिथेन का रिसाव हुआ बताया जा रहा है। रिसाव के चलते राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत दलों को बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। सुरंग के भीतर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम रह गया था। इस कारण कई बेहोश हो गए थे। फंसे लोगों को निकालने के लिए हरसंभव प्रयास हो रहे हैं। सुरंगों के लिए किए जाने वाले भीषण विस्फोटों को भूस्खलन एक बड़ा कारण माना जा रहा है। नामची जिले में जल विद्युत ऊर्जा निगम तीस्ता छह परियोजनाओं के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। समूचे हिमालय में घट रही ऐसी घटनाएं पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इस सुरंग के अलावा सिक्किम के ऊंचाई वाले नगरों व ग्रामों तक पहुँच आसान बनाने के लिए अनेक सुरंगें निमार्णाधीन हैं। इनमें 578 मीटर लंबी एक सुरंग मंगन जिले की सीमा में गंगटोक-चुंगथांग राजमार्ग पर बन रही है। दूसरी प्रमुख सुरंग सिवोक-रंग्पो है। इसे पाक्योंग जिले में भारत-तिब्बत तक बनाया जा रहा है। यह सुरंग सीमा तक सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। मालूम हो, बीते साल फरवरी 2025 में तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले के डोमलपेटा गांव में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) परियोजना की निमार्णाधीन सुरंग में फंसे आठ लोगों का जीवन बचाने में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। 42 किमी लंबी यह सुरंग बनने के बाद दुनिया की सबसे लंबी पानी की सुरंग कहलाएगी। 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निमार्णाधीन सुरंग का एक हिस्सा भूमि में धंस जाने के कारण 40 मजदूर फंस गए थे। उनके प्राण पिछले कुछ दिनों से संकट में जरूर हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। यह हादसा उत्तरकाशी से 55 किमी दूर निमार्णाधीन सिल्क्यारा-पोलगांव सुरंग के भीतर हुआ था। यह हादसा भू-स्खलन के कारण सुरंग का 15 मीटर हिस्सा जमीन में धंस जाने के कारण घटित हुआ था। बरसात के मौसम में सुरंगें मलबे और पानी से भर जाती हैं। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेट माइनर्स अर्थात चूहों की तरह खदान खोदने वाले विशेषज्ञ खनिक इस काम को अंजाम तक पहुँचा पाते हैं। यही सिक्किम के लोगों को बचने के काम में जुटे हैं। बचाव दल रोबोटिक कैमरों की मदद से लोगों तक बमुश्किल पहुँच पता है। ये थर्मल फिशिंग नौका से सुरंग के अंदर पहुँचते हैं। वर्तमान में देशभर के पहाड़ों की पारिस्थितिकी की अनदेखी करके सड़कों, रेल लाइन, नहरों के पानी की निकासी, नदी जोड़ों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय के शिखरों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक पहाड़ों को खोदा जा रहा है। इन कठिन कार्यों को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अनेक दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। समूचे हिमालय क्षेत्र में बीते एक दशक से पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने के परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत संयंत्र और रेल परियोजनाओं की बाढ़ आई हुई है। इन योजनाओं के लिए हिमालय क्षेत्र में रेल गुजराने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में डालने के लिए सुरंगें निर्मित की जा रही हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है। इस आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास का ही परिणाम है कि आज हिमालय ही नहीं, हिमालय के शिखर दरकने लगे हैं, जिन पर गुजराने और से मानव बसाहटें अपने ज्ञान-परंपरा के बूते जीवन-यापन करने के साथ हिमालय और वहां रहने वाले अन्य जीव-जगत की भी रक्षा करते चले आ रहे हैं। हिमालय और पृथ्वी सुरक्षित बने रहें, इस दृष्टि से कृतज्ञ मनुष्य ने अथर्ववेद में लिखे पृथ्वी-सूक्त में अनेक प्रार्थनाएं की हैं। यह सूक्त में राष्ट्रीय अवधारणा एवं वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को विकसित, पोषित एवं फलित करने के लिए मनुष्य को नीति और धर्म से बांधने की कोशिश की हैं। लेकिन हमने कथित भौतिक सुविधाओं के लिए अपने आधार को ही नष्ट करने का काम आधुनिक विकास के बहाने कर दिया।

हृदयनारायण दीक्षित
प्रशासन तंत्र लोक कल्याणकारी कामों का लाभ आमजनों तक ले जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासन तंत्र को सक्रिय किया है। प्रशासमंत्री नीति व निर्णयों में तेज रफ्तार गतिशील हैं। वे सारी कार्य संस्कृति बदल रहे हैं। आखिरकार सभी सुधारों का अंतिम उपकरण प्रशासन तंत्र है। नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासन तंत्र द्वारा ही होता है। नौकरशाही और प्रशासनिक तंत्र में जड़ता है। जिम्मेदार अधिकारी भी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में जनता से दूरी बनाए रखते हैं। देश में अधिकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों के मध्य अच्छे सम्बंध नहीं हैं। जनप्रतिनिधियों और

विनोद सिंह
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है।वही वह सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है,जहाँ 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएँ, समस्याएँ,आशाएँ और भविष्य नीति एवं कानून का स्वरूप ग्रहण करते हैं। संसद केवल विधेयकों को पारित करने की संस्था नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने,विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देने और राष्ट्रीय सहमति निर्मित करने का संवैधानिक मंच है।संसद चलती है तो लोकतंत्र जीवंत दिखाई देता है,सरकार उत्तरदायी बनती है, विपक्ष प्रभावी भूमिका निभाता है और जनता का विश्वास मजबूत होता है।किंतु जब यही संसद बार-बार हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ जाती है,तब केवल कार्यवाही ही नहीं रुकती, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास की गति और जनविश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान मानसून सत्र एक बार फिर इसी चिंता को सामने लेकर आया है।सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक तर्कों के साथ आमने-सामने हैं। विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा और जवाबदेही की माँग कर रहा है, जबकि सरकार संसदीय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही संचालित करने की बात कह रही है। परिणाम यह है कि लोकसभा और राज्यसभा,दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। प्रश्न यह नहीं कि किसका पक्ष सही है और किसका गलत; वास्तविक प्रश्न यह है कि इस राजनीतिक टकराव की कीमत कौन चुका रहा है इसका उत्तर स्पष्ट है-देश का कर्ददाता।

संसद की कार्यवाही का प्रत्येक मिनट अत्यंत मूल्यवान है। उपलब्ध संसदीय आकलनों के अनुसार संसद के संचालन पर प्रति मिनट औसतन लगभग ढाई लाख रुपये का सार्वजनिक व्यय होता है।अर्थात एक घंटे की कार्यवाही पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये और एक पूर्ण कार्यदिवस पर लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये तक खर्च होते हैं। इस राशि में संसदों के वेतन एवं भत्ते, संसद सचिवालय का प्रशासनिक व्यय, सुरक्षा व्यवस्था,अनुवाद सेवाएँ, प्रत्यक्ष प्रसारण,सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, बिजली, रखरखाव तथा हजारों कर्मचारियों का वेतन सम्मिलित होता है।संसद चले या न चले,यह व्यय निरंतर होता रहता है। इसलिए जब कार्यवाही

अर्थशास्त्र में प्रशासन तंत्र का खूबसूरत विवरण है। सिंधु घाटी सभ्यता (2200 ई0पूर्व से 1750 ई0पूर्व तक) के प्रशासन को।लर व पिगाट जैसे विद्वानों ने भी सुगठित बताया है। उत्तर वैदिक काल व वैदिक काल का प्रशासन समाज के साथ एकताबद्ध और उत्तरदायी था। अंग्रेजी शासकों ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रशासन तंत्र बनाया था। अंग्रेज सरकारों ने भी प्रशासनिक सुधारों के लिए कई आयोग बनाए थे। प्रशासन ही सत्ता चलाने का उपकरण था। वे स्वाभाविक ही प्रशासनिक सुधारों पर सजग थे लेकिन स्वतंत्र भारत में लम्बे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधारों पर कोई ठोस काम नहीं किया। प्रशासन परम स्वतंत्र

होने की स्थिति का उपभोग करता आया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका व नीति निदेशक तत्व सरकार व प्रशासन तंत्र के मार्गदर्शक हैं। वे सुस्थापित विधि नहीं बल्कि सरकार व प्रशासन के कामकाज की आत्मा है। प्रशासन तंत्र इन सूत्रों से नहीं जुड़ता। स्वतंत्र भारत (1951) में प्रशासन की कार्यशैली पर एन0डी0 गौरवाला की रिपोर्ट लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन नाम से आई। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी लोकतंत्र स्पष्ट, कुशल व निष्पक्ष प्रशासन के अभाव में सफल नियोजन नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट में अनेक उपयोगी सुझाव थे लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ। 1952 में केन्द्र ने प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए पाल एपिलबी की नियुक्ति

है। आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, डिजिटल नवाचार और वैश्विक नेतृत्व निश्चित रूप से गर्व के विषय हैं। लेकिन यदि हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति संयुक्त परिवार कमजोर हो जाएगी, तो यह प्रगति अशुभी रह जाएगी। विश्व भारत से केवल आर्थिक शक्ति की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उन जीवन-मूल्यों की भी अपेक्षा करता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस सभ्यता को जीवित रखा है। विश्वगुरु वही बन सकता है जो अपने परिवारों को भी मजबूत रख सके। जिस समाज में माता-पिता उपेक्षित हों, बुजुर्ग अकेले हों, बच्चे भावनात्मक रूप से असुरक्षित हों और पति-पत्नी विश्वास के संकट से जूझ रहे हों, वह केवल आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, सांस्कृतिक महाशक्ति नहीं। समय आ गया है कि परिवारों में पुनः संवाद की संस्कृति विकसित की जाए। सप्ताह में कुछ समय ऐसा हो जब पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठे। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी मिलें। विद्यालयों में जीवन-मूल्य और भावनात्मक शिक्षा को महत्व दिया जाए। विवाह-पूर्व परामर्श, पारिवारिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परिवार में बुजुर्गों की भूमिका को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए, क्योंकि वे केवल अतीत के प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य के मार्गदर्शक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी किसी न्यायिक टिप्पणी भर नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी का शंखवाह है। यदि हमने अभी भी अपने परिवारों को बचाने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले वर्षों में केवल अदालतों में मुकदमे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि समाज की संवेदनाएं भी समाप्त होती जाएंगी। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है- वसुधैव कुटुम्बकम्। लेकिन जो समाज अपने ही परिवार को नहीं बचा पाएगा, वह पूरी दुनिया को परिवार कैसे मान सकेगा? आज आवश्यकता नई इमारतें बनाने की नहीं, बल्कि बिखरते घरों को जोड़ने की है।

आज हम की जगह मैं ने ले ली है। अधिकारों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों का स्मरण बहुत कम होता है। रिशतों में बढ़ता अहंकार भी विघटन का बड़ा कारण है। पति-पत्नी दोनों अपने-अपने तर्कों को अंतिम सत्य मानने लगे हैं। कोई झुकना नहीं चाहता। जबकि भारतीय परंपरा ने सिखाया था कि झुकना हार नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की सबसे बड़ी जीत है। भोजन की मेज पर संवाद समाप्त हो गया है। आंखों में आंखें डालकर बातें करने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। इससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है और अकेलापन बढ़ रहा है। इस पूरे संकट की जड़ केवल अधुनिकता नहीं है। समस्या आधुनिकता के असंतुलित और अधानुकूलन में है। पश्चिम से हमने तकनीक तो अपनाई, लेकिन उसकी सामाजिक चुनौतियों से सीख नहीं ली। अब पति और पत्नी के बीच तीसरा आना आम बात हो गयी है, और यही तीसरा समस्या की जड़ है। इस तरह के अवैध रिशतों ने त्रासद घटनाओं को जन्म दिया है। भारतीय परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी-मैं से पहले हम का भाव।

की। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव थे। लेकिन जड़ता नहीं टूटी। स्वाधीनता के 19 बरस बाद पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) बना। मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे, वे मंत्री हो गए। आयोग ने हनुमैया की अध्यक्षता में काम बढ़ाया। आयोग का पहला प्रतिवेदन नागरिकों की व्याप्त दूर करने की समस्या शीर्षक से 20 अक्टूबर 1966 में आया। प्रशासन बनाम आमजन की व्याथा से पूरा देश पीड़ित है लेकिन इस महत्वपूर्ण बिन्दु की उपेक्षा हुई। आयोग ने केन्द्रीय प्रशासन व राज्य प्रशासन पर अलग-अलग सुझाव दिये।

स्मृतियों में जिम कॉर्बेट

प्रयाग पाण्डे
प्रकृति के सजग चित्तेरे, वन्यजीव विज्ञानी, शिकार कथा लेखक और प्रसिद्ध शिकारी जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती 25 जुलाई के साथ खामोशी के साथ गुजर गई। 71 वर्ष पूर्व उनकी आत्मा अनंत में विलीन हो चुकी है। इसके बावजूद नेकदिली और भलमनसाहत के चलते जिम कॉर्बेट भारत के सामाजिक जीवन का अटूट हिस्सा बने हुए हैं। जिन लोगों ने जिम कॉर्बेट को कभी देखा नहीं, वे भी गरीबों से अगाध प्रेम करने वाले नेक दिल ईसान के रूप में जिम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के पुरखे मूलतः अयरिश नागरिक थे। कॉर्बेट का कुटुंब तीन पीढ़ियों तक भारत में रहा। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई,1875 को नैनीताल में हुआ था। इस दृष्टि से वे जन्म से भारतीय थे। संस्कारों से भी। जिम के पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट था। वे नैनीताल के हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उनकी मां का नाम मैरी जेन कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट की ख्याति कुशल शिकारी और शिकार कथा लेखक के रूप में है, लेकिन यह उनके व्यक्तित्व का अधूरा पक्ष है। वे अचूक निशानेबाज तो थे ही, इसी से उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। इसके इतर वे गरीबों के प्रति अत्यधिक उदार और मानवीय गुणों से भरे संवेदनशील भलमानुष भी थे। उन्होंने अनेक बार स्वयं के जीवन को गंभीर संकट में डालकर मानव जीवन की रक्षा की। इसी भलमनसाहत के चलते जिम कॉर्बेट के जन्म से ईसाई होने के बावजूद उत्तराखंड की धर्मभूरी जनता ने उन्हें 'गोरा साधु' की संज्ञा दी थी। जिम कॉर्बेट ने कबीर डेढ़ हजार लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार दर्जन भर से अधिक खूंखार नरभक्षियों का अत्यंत साहस और बहादुरी के साथ मुकाबला किया। अपने प्राणों की परवाह किए बिना नरभक्षियों से लड़े। जान आदमखोरों के सामने देश- विदेश के अनेक नामचीन निशानेबाजों ने हथियार डाल दिए थे, जिम कॉर्बेट ने अकेले उनका खाम्ता कर उत्तराखंड के निवासियों को नरभक्षियों के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस वजह से उत्तराखंड का जनमानस जिम कॉर्बेट को चमत्कारिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति मानता था। जिम कॉर्बेट के जीवन का अधिकांश हिस्सा कुदरत के निकट बीता। उन्होंने जंगल को अपने भीतर सोख लिया था। उनका संपूर्ण जीवन प्रकृति के सूक्ष्म और गहन रहस्यों को जानने और आत्मसात करने में बीता। स्वअर्जित जंगल ज्ञान के बूते ही वे प्रकृति के ज्ञाता बने और दुर्दांत नरभक्षियों को मारने में सफल हुए। जिम कॉर्बेट का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे प्रकृति विज्ञानी, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं मशहूर शिकारी थे साथ ही वन्यजीव रक्षक भी। उन्होंने रेलवे में नौकरी की। सेना में भी सेवाएं दीं। जिम कॉर्बेट को सेना में कर्नल की पदवी से नवाजा गया था। वे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भी रहे। जिम कॉर्बेट ने 1907 से 1940 के कालखंड में नैनीताल नगर पालिका के सदस्य, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया। वे ठेकेदार भी थे और संपत्ति एजेंट भी। जिम सिद्धहस्त लेखक भी थे और प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर भी। जिम की तत्कालीन अंग्रेज शासकों के साथ निकटता भी थी और वे भारत के गरीबों के अजीज दोस्त एवं हमदर्द भी थे।



बिना किसी विधायी उपलब्धि के स्थगित हो जाती है,तब जनता के धन का प्रत्यक्ष नुकसान होता है। मानसून सत्र के शुरूआती दिनों में दोनों सदनों की कार्यवाही बार- बार बाधित होने से करोड़ों रुपये मूल्य का संसदीय समय व्यर्थ चला गया। प्रारंभिक दिनों में अनेक बार सदन कुछ ही मिनटों में स्थगित करने पड़े। इससे न केवल प्रश्नकाल प्रभावित हुआ, बल्कि शून्यकाल,विधायी कार्य और जनहित के अनेक विषय भी चर्चा से वंचित रह गए। संसद की कार्यवाही हो होने वाला व्यय तो यथावत जारी रहा,किंतु सही है और किसका गलत; वास्तविक प्रश्न यह है कि इस राजनीतिक टकराव की कीमत कौन चुका रहा है इसका उत्तर स्पष्ट है-देश का कर्ददाता।

संसद की कार्यवाही का प्रत्येक मिनट अत्यंत मूल्यवान है। उपलब्ध संसदीय आकलनों के अनुसार संसद के संचालन पर प्रति मिनट औसतन लगभग ढाई लाख रुपये का सार्वजनिक व्यय होता है।अर्थात एक घंटे की कार्यवाही पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये और एक पूर्ण कार्यदिवस पर लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये तक खर्च होते हैं। इस राशि में संसदों के वेतन एवं भत्ते, संसद सचिवालय का प्रशासनिक व्यय, सुरक्षा व्यवस्था,अनुवाद सेवाएँ, प्रत्यक्ष प्रसारण,सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, बिजली, रखरखाव तथा हजारों कर्मचारियों का वेतन सम्मिलित होता है।संसद चले या न चले,यह व्यय निरंतर होता रहता है। इसलिए जब कार्यवाही

छोड़कर टकराव का रूप ले लेती है। लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता केवल आँकड़ों का विषय नहीं है। उसके पीछे करोड़ों नागरिकों की अपेक्षाएँ जुड़ी होती हैं। संसद में प्रत्येक दिन किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, पर्यावरण,महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और राज्यों से जुड़े अनेक प्रश्न उठाए जाने होते हैं। प्रश्नकाल में संसद सरकार से जवाब माँगते हैं। शून्यकाल में तत्काल जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। स्थायी समितियों की अनुशंसाओं पर चर्चा होती है।नए विधेयकों पर बहस होती है। किंतु जब सदन बार-बार स्थगित हो जाता है, तब यह पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है।लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है। एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। सरकार से कठोर प्रश्न पृष्ठना,नीतियों की समीक्षा करना और जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाना विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व है कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी रहे और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। किंतु विरोध और व्यवधान में मौलिक अंतर है। विरोध लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि निरंतर व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। संसद में यदि बहस के स्थान पर केवल नारे, पोस्टर और स्थगन दिखाई दें

तो सबसे बड़ी क्षति संवाद की संस्कृति को होती है। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति हमेशा उसकी संवाद क्षमता रही है। संसद के इतिहास में अनेक अवसर ऐसे आए,जब तीखे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय सर्वसम्मति अथवा व्यापक चर्चा के बाद निर्गत बाधित होना केवल वर्तमान राजनीतिक विवाद का विषय नहीं,बल्कि चिंता का संकेत है।संसद की कार्यवाही बाधित होने का सबसे बड़ा नुकसान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भी होता है।संसद वह मंच है जहाँ सरकार का मंच नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र का लोकतांत्रिक संस्थान है।वर्तमान परिस्थितियाँ इसलिए भी चिंता उत्पन्न करती हैं क्योंकि भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।आधारभूत संरचना, रेल, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी,अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण और निवेश जैसे क्षेत्रों में देश अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।ऐसे समय में संसद का प्रत्येक कार्यदिवस राष्ट्रीय विकास की दिशा में पुर करने वाला होता है। यदि वही समय राजनीतिक टकराव में व्यतीत हो जाए, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान विधायी कार्यों पर नहीं,बल्कि दीर्घकालिक नीति-निर्माण पर भी पड़ता है।

परिवार परम्परा एवं बिखरते रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

ललित गर्ग
परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, धैर्य और संस्कारों का जीवंत विद्यालय है। जब इस विद्यालय की नींव कमजोर होने लगती है तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। देश के बहुचर्चित सोमन घुववंशी हनीमून मर्डर प्रकरण की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्ति की गई चिंता केवल एक अपराध पर की गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के बदलते चरित्र का गहन सामाजिक विश्लेषण थी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले ने जिस पीड़ा के साथ कहा कि संयुक्त परिवार लोगों को धैर्य, संयम, सहनशीलता और समायोजन सिखाते थे, वहीं आज एकल परिवारों में अक्साद, असहिष्णुता और संबंधों का विघटन बढ़ रहा है, वह हमारे समय का कटु सत्य है। माता-पिता और संतान, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा। ऐसे घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु संवेदनाएं सिकुड़ती जा रही हैं। संवाद कम हो गए हैं और स्क्रीन का समय बढ़ गया है। परिणामस्वरूप रिश्ते धीरे-धीरे औपचारिकता में बदलते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में विवाह से पहले अथवा विवाह के कुछ ही दिनों बाद हुई इन नृशंस हत्याओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के पतन का संकेत है। जिन परिवारों में धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहीं जीवन का सबसे बड़ा अभाव विश्वास और संतोष का था। संत कबीर का यह



वचन आज पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है- जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। भौतिक संपन्नता कभी भी मानसिक शांति और रिश्तों की ऊष्मा नहीं खरीद सकती। भारतीय संस्कृति ने परिवार को केवल सामाजिक संस्था नहीं माना, बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन-मूल्यों का परिवार को शक्ति से हल्का हो जाता था। आज यह सुरक्षा-कवच तेजी से टूट रहा है। महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में पति-पत्नी दोनों कार्यश्रल पर व्यस्त हैं। बच्चों का बचपन मोबाइल, टैबलेट और परेलू सहायिकाओं के भरोसे बीत रहा है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद नहीं, मोबाइल थमा दिया जाता है। यह सुविधा का और संतोष का था। संत कबीर का यह

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि भावनाओं का विकल्प गैजेट्स नहीं हो सकते, हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक चेतावनी है। डिजिटल क्रांति ने जीवन का सरल अवश्य बनाया है, लेकिन यदि तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाए तो वह संबंधों की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। आज परिवार एक ही कमरे में बैठकर भी अलग-अलग दुनिया में खोया रहता है। भोजन की मेज पर संवाद समाप्त हो गया है। आंखों में आंखें डालकर बातें करने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। इससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है और अकेलापन बढ़ रहा है। इस पूरे संकट की जड़ केवल अधुनिकता नहीं है। समस्या आधुनिकता के असंतुलित और अधानुकूलन में है। पश्चिम से हमने तकनीक तो अपनाई, लेकिन उसकी सामाजिक चुनौतियों से सीख नहीं ली। अब पति और पत्नी के बीच तीसरा आना आम बात हो गयी है, और यही तीसरा समस्या की जड़ है। इस तरह के अवैध रिश्तों ने त्रासद घटनाओं को जन्म दिया है। भारतीय परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी-मैं से पहले हम का भाव।

पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ

योगेश कुमार

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सफाईकर्मियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने स्वच्छ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में सफाईकर्मियों के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनके साथ सहभोज भी किया। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सुद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, निगमयुक्त संजीव खिरवार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह नई व्यवस्था घर-घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाएगी तथा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर



दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम के समक्ष पर्याप्त संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव था। कचरा संग्रहण वाहनों की कमी, जर्जर ढलाव और सीमित मशीनरी के कारण स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी। अब इन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक कम्पैक्टर युक्त ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो न

केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं बल्कि देखने में भी आकर्षक हैं। यह व्यवस्था केवल पश्चिमी दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू की जाएगी। यह परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.50 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को 31

अगस्त 2026 तक जोड़ा जाएगा। स्वच्छता व्यवस्था के लिए 917 अत्याधुनिक वाहनों और आधुनिक कचरा संग्रहण संसाधनों की तैनाती की गई है, जिससे हर घर से समयबद्ध और प्रभावी कचरा संग्रहण सुनिश्चित होगा। इसमें संकरी गलियों तक आसान पहुंच के लिए 225 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर, 52 कम्पैक्टर, 41 हुक लोडर, 28 टाटा 407, 10 डम्पर, 6 बिन वॉशर, 123 एफसीटीएस

बिन और 1,300 लीटर क्षमता वाले 1.1 सीबीएम बिन शामिल हैं। इन अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से प्रत्येक घर से शत-प्रतिशत, समयबद्ध और प्रभावी कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री आशीष सुद ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के माध्यम से घर-घर से समयबद्ध कचरा संग्रहण, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब घरों से कचरा केवल एक बार नहीं, बल्कि सुबह और शाम, दिन में दो बार उठाया जाएगा। वाहनों और निगम की उन्नत व्यवस्था के माध्यम से राजधानी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने का कार्य भी अभूतपूर्व गति से चल रहा है। वर्षों से राजधानी पर बोझ बने इन लैंडफिल स्थलों में लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले कूड़े के पहाड़ों में से 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कूड़ा मुक्त किया जा चुका है।

उपराज्यपाल ने स्कूलों में बच्चों के विकास और सुरक्षा पर दिया जोर



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को पीएचडी चैंबर हाउस में हर्सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026' पर आयोजित नेशनल समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्ति माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और

अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। देश की राजधानी होने के नाते, सुरक्षित, समावेशी और मुश्किल हालात का सामना करने में सक्षम सीखने का माहौल बनाने में मिसाल कायम करने की दिल्ली की एक विशेष जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने कहा कि 'नेशनल मॉडल स्कूल सेप्टी टूलकिट' के लॉन्च को भी देखा। स्कूलों में तैयारी और बचाव की संस्कृति को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका लॉन्च इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली इस जुलाई में 'बाल सुरक्षा माह' मना रही है, जिसके तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए कई पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुझे अपने दादाजी, सरदार तेजा सिंह समुंद्री की भी याद आई।

श्रद्धा वाकर हत्याकांड: डीएनए रिपोर्ट के बाद अब पुलिस अधिकारी की होगी गवाही

नई दिल्ली। श्रद्धा वाकर मर्डर केस में सांकेतिक कोर्ट में सब-इंस्पेक्टर संदीप का बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 29 मई को मुकदमे में तेजी लाने के लिए श्रद्धा वाकर मर्डर केस को सुनवाई 20 जुलाई से 27 जुलाई तक प्रतिदिन करने का फैसला किया गया था। आठ जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई की एक तारीख रद्द कर दी थी, क्योंकि आरोपित की 20 जुलाई को एमए (सोशियोलॉजी) की परीक्षा थी। यह परीक्षा तिहाड़ जेल परिसर में स्थित इन्सु सेंटर में होनी थी। एक दिन पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवारिंदर सिंह जग्गी ने अभियोजन पक्ष के गवाह वीआर गिरनार का मुख्या बयान (एग्जामिनेशन-इन-चीफ) दर्ज किया। उनसे जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) बाद में की जाएगी।



कोर्ट में क्या बोले थे डॉ. गिरना ? सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे और शिकायतकर्ता की वकील सीमा समुद्धि कुशवाहा मौजूद थीं। आरोपित आफताब अमीन पूनावाला का प्रतिनिधित्व वकील अक्षय भंडारी कर रहे हैं। कोर्ट के सामने बयान देते हुए डॉ. गिरनार ने इस केस में की गई बायोलॉजिकल और डीएनए जांच के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैपल

(एग्जिबिट्स) 23 दिसंबर, 2022 को मिले थे और रिपोर्ट तीन जनवरी, 2023 को तैयार की गई थी। सबूत पेश करने के दौरान, उन्होंने पुष्टि की कि सैपल की जांच, दस्तावेजीकरण, सीलिंग और हैंडलिंग तय प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। बता दें कि अभियोजन पक्ष के कुल आठ गवाहों से पुछताछ की जानी है। 13 गवाहों के मुख्य बयान आंशिक रूप से दर्ज किए जा चुके हैं और 12 गवाह ऐसे हैं।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने छात्रों पर लग रहे आरोपों को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली। पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की पत्नी गीताजलि जे आंग्मो ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर लगाए जा रहे आरोपों पर चिंता जाहिर की है। गीताजलि आंग्मो ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, "एक शिक्षक के तौर पर, मीडिया में अपने छात्रों की छवि खराब होते देखना मेरे लिए बहुत दुखद है। ये छात्र जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को दोषी ठहराने के बजाए उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए था। हमारे बच्चे सुरक्षा के हकदार हैं, न कि उन्हें विलेन के तौर पर दिखाए जाने के। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए।" उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अगर दिल्ली में कहीं और हिंसा की खबरें आती हैं, तो कृपया बिना सबूत के उन्हें इस आंदोलन से न जोड़ें जो लोग इन युवाओं को सच में जानते हैं, उन्होंने इनका असाधारण धैर्य, अनुशासन और संयम देखा है।

'देश का युवा अराजकता का औजार नहीं, राष्ट्र निर्माता है' - बांसुरी स्वराज

बांसुरी स्वराज ने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने 'संसद चलो' का आह्वान किया और बिना अनुमति संसद की घेराबंदी की कोशिश की। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने संयम बरता और स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कॉंग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार ने पूरे आंदोलन के दौरान संवेदनशील रवैया अपनाया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई दखल नहीं दिया। देश में सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का युवा अराजकता का औजार नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्र निर्माता है। बुधवार भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बांसुरी स्वराज ने कहा कि आंदोलन के संयोजक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी 21 दिनों तक जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे



रहे। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, उन्हें नहीं हटाया गया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने 'संसद चलो' का आह्वान किया और बिना अनुमति संसद की घेराबंदी की कोशिश की। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने संयम बरता और स्थिति को संभालने का

प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संसद जैसी संस्थाओं का सम्मान सर्वोपरि है। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि केंद्र सरकार शुरू से ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार थी। उन्होंने बताया कि जब प्रदर्शनकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने

पहुंचे, तब उनके पास मांगों की कोई लिखित सूची नहीं थी। नड्डा ने उन्हें अपनी मांगें लिखित में देने को कहा, जिसके बाद सूची तैयार करने में करीब ढाई घंटे लगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठक में स्पष्ट किया था कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी और प्रदर्शन समाप्त करने की भी अपील की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने उस समय आंदोलन खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गए। बांसुरी स्वराज ने आंदोलन के दौरान भ्रामक दावे किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे आरोप लगाए गए जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था।

डीयू व उससे संबद्ध कालेजों में महिला सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने की मांग

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में 28 जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र 2026-27 से पहले महिला छात्राओं और शिक्षिकाओं की सुरक्षा को लेकर फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। संगठन ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखकर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस तथा डीयू से संबद्ध कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला पुलिस की तैनाती और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। फोरम के अध्यक्ष प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि देशभर में चल रहे विभिन्न आंदोलनों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना

समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को नए छात्रों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान कॉलेजों के बाहर महिला पुलिस और महिला सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जानी चाहिए तथा पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होनी चाहिए। प्रो. सुमन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों के दौरान महिला शौचालयों एवं ग्रीन रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसी तरह नियमित दिनों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अग्रिम घटना को रोका जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से यह भी मांग की कि सांध्यकालीन कॉलेजों और प्रयोगशालाओं में छात्राओं एवं महिला शोधार्थियों की कक्षाओं का समय शाम 7 बजे तक सीमित किया जाए।

पटियाला हाउस कोर्ट के पीछे आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन, नागरिकों को मिलेंगी बेहतर स्वच्छता सुविधाएं

ओमप्रकाश

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के पीछे नवनिर्मित आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनडीएमसी के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी अपने क्षेत्र में स्वच्छ, आधुनिक, सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 42.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एनडीएमसी क्षेत्र में वर्तमान में 364 सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां संचालित हैं। इनमें 291 सार्वजनिक शौचालय, 40 सामुदायिक शौचालय तथा 33 सार्वजनिक मृशालय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के



पीछे स्थित पुराने लगभग 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले सार्वजनिक शौचालय को बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर हटाकर लगभग 50 वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए शौचालय का निर्माण कराया गया है। लगभग 22 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य पांच माह में पूरा किया गया। चहल ने बताया कि नए

सार्वजनिक शौचालय में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। पुरुष ब्लॉक में तीन वाटर क्लोसेट और पांच सेंसर आधारित सुविधाएं तथा महिला ब्लॉक में तीन वाटर क्लोसेट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सेंसर आधारित सुविधाओं से पानी की बचत होगी और संपर्क रहित उपयोग से स्वच्छता का

स्तर भी बेहतर होगा। आधुनिक वेंटिलेशन और अन्य सुविधाओं के कारण यह शौचालय अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से पटियाला हाउस कोर्ट आने वाले अधिवक्ताओं, वार्दकारियों, न्यायालय कर्मचारियों, आगंतुकों और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने कहा कि परिषद भविष्य में भी सार्वजनिक शौचालयों सहित अन्य नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्य जारी रखेगी, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक सुविधाओं का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और उन्हें स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

सिविल लाइंस स्थित मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर स्थायी पंप हाउस का शुभारंभ

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना में बाढ़ के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर स्थायी पंप हाउस का शुभारंभ किया। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब तक जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ने पर मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर बंद किया जाता था, तब वर्षा जल की निकासी के लिए हर बार अस्थायी पंप लगाने पड़ते थे। अब इस स्थायी पंप हाउस के निर्माण से जल निकासी की व्यवस्था स्थायी रूप से सुदृढ़ होगी, जिससे बाढ़ के दौरान वर्षा जल को तेजी और प्रभावी ढंग से यमुना में प्रवाहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक पंप हाउस में 75 हॉर्सपावर (एचपी) के 3 सबमर्सिबल पंप और 35 एचपी का 1 सबमर्सिबल पंप स्थापित किया गया है, जिनकी कुल पंपिंग क्षमता लगभग 2500 किलोलीटर प्रति घंटा है। मंत्री ने कहा कि बिजली अपूर्णता बाधित होने की स्थिति में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए 250 केवीए क्षमता का डीजी सेट लगाया गया है। साथ ही पंपों के सुचारु, सुरक्षित एवं ऊर्जा-कुशल संचालन के लिए एनजी एफिशिएंट सॉफ्ट स्टार्टर पैनल भी स्थापित किया गया है।

आईआईटी खड़गपुर में अंतः विषयक अनुसंधान व शैक्षणिक सहयोग को लेकर हुआ समझौता

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। लीड्स यूनिवर्सिटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने आज अंतः विषयक अनुसंधान, शैक्षणिक सहयोग और नवाचार पर केंद्रित एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए दिल्ली स्थित ऑस्ट्रेलिया एंबेसी में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाज, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है। यह जानकारी एक विज्ञापित के जरिए दी गई है। विज्ञापित के मुताबिक, इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से वित्तपोषित एक सोड फंड स्थापित करेंगे, जिसे प्रत्येक संस्थान द्वारा अधिकतम 50,000 अमेरिकी डॉलर तक के समान योगदान से समर्थन दिया जाएगा। यह कोष शोधकर्ताओं को पायलट परियोजनाओं

पर कार्य करने, नवाचारी विचारों का परीक्षण करने और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण अवसरों के लिए प्रस्ताव विकसित करने में सक्षम बनाएगा। लीड्स यूनिवर्सिटी ने पहले ही अपनी ओर से निर्धारित योगदान आवंटित कर उसका उपयोग साझेदारी के अंतर्गत सहयोगात्मक गतिविधियों के प्रारंभिक चरण को समर्थन देने के लिए कर लिया है, जबकि आईआईटी खड़गपुर ने चालू वर्ष के लिए अपना योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह एमओयू अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। दोनों संस्थान संयुक्त स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान-आधारित शिक्षण पहलों के विकास के अवसर तलाशेंगे, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को विविध शैक्षणिक दृष्टिकोणों तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षण अनुभवों तक पहुंच प्राप्त होगी। लीड्स यूनिवर्सिटी में



अंतरराष्ट्रीयकरण के निदेशक प्रो. वासिलिस् साहोसिस ने कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों के लिए एक उत्साहजनक नया कदम है और यह

दशर्ती है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कितना मूल्यवान है। अपनी-अपनी विशेषज्ञताओं को एक

साथ लाकर हम विश्वस्तरीय अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों का समर्थन कर सकते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में

वास्तविक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। हम आईआईटी खड़गपुर के साथ एक गतिशील और दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की आशा करते हैं, जो

ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और यूके तथा भारत दोनों की शैक्षणिक समुदायों के लिए नए अवसर सृजित करेगा। आईआईटी खड़गपुर के डीन (अंतरराष्ट्रीय संबंध), प्रो. आनंदरूप भट्टाचार्य ने कहा कि आईआईटी खड़गपुर हमेशा से मानता रहा है कि वैश्विक साझेदारियां अनुसंधान उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और परिवर्तनकारी शैक्षणिक अवसरों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी के साथ यह सहयोग हमारी पूरक क्षमताओं और साझा महत्वाकांक्षाओं को एक साथ लाता है, जिससे हमें प्रभावशाली अनुसंधान करने, प्रतिभाओं को विकसित करने और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। इस साझेदारी के माध्यम से हम नए ज्ञान का सृजन करने और ऐसे समाधान विकसित करने की आशा करते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दें।

ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। स्पेशल टास्क फोर्स नोएडा सुनिट ने शेल कंपनियों के जरिए संचालित हो रहे अंतरराष्ट्रीय हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पदार्पण किया है। एसटीएफ ने एक चीनी नागरिक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिक का छह वर्ष पहले ही बीजा समाप्त हो चुका था। आरोप है कि यह गिरोह नोएडा से दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये का अवैध लेन-देन कर रहा था। एसटीएफ मनी ट्रेल खंगालने के लिए ईडी और आयकर विभाग से भी समन्वय

करेगा। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्र के मुताबिक, बुधवार रात करीब 10 बजे सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिल्वर सिटी से चीनी नागरिक लियाओ लानाहुई, गाजियाबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार और औरैया निवासी कौशलेंद्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के कब्जे से पांच लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 10 मोहरे, 11 चेकबुक, दो चीनी पासपोर्ट, एक चीनी पहचान पत्र, पैन कार्ड और विभिन्न बैंकों के करीब 4.72



करोड़ रुपये के चेक बरामद किए गए हैं। लियाओ लानाहुई वर्ष 2018 में भारत आया था, तब से सेक्टर-83 स्थित वाइटीएल मैनुफैक्चरिंग कंपनी का संचालन कर मोबाइल कवर बनावा रहा था।

आरोप है कि चीन से आयातित कच्चे माल की कीमतों में हेरफेर कर तैयार माल दिल्ली के करोलबाग, नेहरू प्लेस सहित अन्य बाजारों में अंडर इनवायसिंग (टैक्स से बचने को या बिना घोषित किए गए फंड को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार चुपके से भेजना) से बेचा जाता था। इससे बची रकम को हवाला के जरिए चीन भेजा जाता था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि यह गिरोह शेल कंपनियां बनाकर वित्तीय अपराध कर रहा है। सत्यापन के बाद कंपनी के

संचालक लियाओ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दस्तावेज न दे पाने पर उसके सेक्टर-93 स्थित फ्लैट पर छापा मार कर कई कंपनियों की चेकबुक, बैंक दस्तावेज, मोहरें और फर्जी पहचान पत्र मिले। लियाओ के पास से नागालैंड के कोहिमा निवासी सैमुल लोथा के नाम का आधार कार्ड भी मिला, जिस पर उसकी फोटो लगी थी। उसका बीजा 2020 में ही खत्म हो चुका था। फेज- दो कोतवाली में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

वाह रे सिस्टम! नोएडा के सेक्टर-80 में ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन होम, नीचे चल रही शराब की दुकान

किशोर न्याय अधिनियम और आबकारी नियमों का उल्लंघन। मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी को हटाने हेतु पत्र

नोएडा। आबकारी नीति कमाई का जरिया बनती नजर आ रही है। 100 मीटर के दायरे में कई शराब के ठेके संचालित हो रहे हैं। कई स्थानों पर फुटपाथ और अस्थायी टीन शेड की दुकानों में शराब बेचने का लाइसेंस दे दिया गया है। नोएडा में फेज-2 के सेक्टर-80 में पहली मंजिल पर बाल संप्रपण गृह (किशोर) हैं। इनके नीचे शराब की दुकान संचालित हो रही है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार-4 ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को शराब की दुकान हटाने के लिए पत्र लिखा है। शिकायत की कॉपी किशोर न्याय समिति की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच, जिला आबकारी अधिकारी को भी प्रेषित की गई है।



अपराधों में शामिल किशोर रहते हैं। मौजूदा समय में यहां पर 102 किशोर रह रहे हैं। बाल संप्रपण गृह के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शराब की दुकान संचालित हो रही है। यह दुकान किशोरों पर दुष्प्रभाव की वजह बन रही है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि यहां रह रहे बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को खतरे में डालने वाली यह दुकान अधिनियम का

निरास स्थान के 200 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक्साइज शापप रूल्स-1968 के नियम-5(4) का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या आवासीय इलाके के निकट नई शराब दुकान खोलने पर रोक लगाई गई है। **प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी** बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बाल गृह के आसपास शराब की उपलब्धता बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। प्रधान मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने लिखा कि बच्चों का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जिला प्रशासन से अपील की गई है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई करे।

गाजियाबाद में 16 साल के किशोर से कराया काम, वेतन मांगा तो नौकरी से निकाला; एफआईआर दर्ज

गाजियाबाद। मेरठ रोड निवासी 16 वर्षीय नाबालिग से रेस्तरां में काम कराने, वेतन न देने और धमकी देने के आरोप में रेस्तरां संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में यूपी बाल आयोग ने पुलिस को मेल पर शिकायत भेजी इसके बाद कविनगर थाने में केस दर्ज किया गया है।

फोन चोरी होने के बाद वेतन मांगने पर नौकरी से निकाला मेरठ रोड निवासी 16 वर्षीय नाबालिग राजनगर सेक्टर-9 स्थित मेक माई चाप रेस्तरां में 15 मई से भोजन, रहने की व्यवस्था और 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 23 मई को रेस्तरां में काम के दौरान उसका



मोबाइल फोन चोरी हो गया। इस पर रेस्तरां संचालक ने नया फोन दिलाने और शिकायत दर्ज कराने का आश्वासन देकर उसे शांत करा दिया। नाबालिग का आरोप है कि बाद में जब उसने अपने मोबाइल और बकाया वेतन के बारे में पूछा तो संचालक ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि संचालक ने वेतन देने से भी मना

कर दिया और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित ने किसी तरह मामले को शिकायत यूपी बाल आयोग में की। इसके बाद आयोग ने सीधे पुलिस अधिकारियों को मेल भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रेस्टरेंट कारोबार के विवाद में दोस्त ने रची हत्या की साजिश, गुरुग्राम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या



साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में देर रात गुरुग्राम के एक रेस्टरेंट संचालक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हिंडन-कनावनी रोड पर अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्त भी गुरुग्राम में रेस्टरेंट संचालक था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने स्वयं पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद रेस्टरेंट संचालक को हिरासत में ले लिया है। आरोपित ने वारदात में शामिल अपने दो साथियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि बुधवार रात करीब एक बजे विजय शर्मा नामक व्यक्ति ने सूचना देकर दी कि बाइक सवार दो बदमाशों ने हिंडन-कनावनी रोड पर उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक युवक का शव चालक के बराबर वाली सीट पर था। उसका सिर डेश बोर्ड पर टिका था। सिर में पीछे से गोली मारी गई थी। कार में खून के कुछ निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोचरी भेज दिया। एसपी ने बताया कि सूचना देने वाला विजय घटनास्थल पर मौजूद था। उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह गुरुग्राम

हत्याकांड में बड़ा खुलासा, माता-पिता की हत्या करने को तौलिए का भी किया इस्तेमाल

संपत्ति विवाद में बेटों ने की माता-पिता की हत्या। मुख्य आरोपी छोटे बेटे ललित ने तौलिए से गला घोंटा। दोनों आरोपी बेटों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

गाजियाबाद। क्रांसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर में संपत्ति विवाद में सोमवार रात माता-पिता की हत्या करने के आरोपित बेटों ललित और दीपक उर्फ विक्की को बुधवार को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। **छोटे बेटे ललित को बताया जा रहा मुख्य आरोपित** वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि घटना के समय छोटा बेटा ललित ज्यदा हमलावर था। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात छोटे बेटे ललित ने सबसे पहले



दीपक उर्फ विक्की भी उसके साथ मौजूद रहा और वारदात में सहयोग करता रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि छोटे बेटे ललित का

स्वभाव काफी उग्र था और परिवार में संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। **दोनों भाइयों ने जताया पछतावा** पुलिस पूछताछ में दोनों भाइयों ने अपने किए पर पछतावा भी जताया है। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। मृतक गंगाशरण के घर पर रिश्तेदारों और परिचितों का आना-जाना लगा रहा। मोहल्ले में भी घटना को लेकर

शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बुधवार को दंपति की अस्थियां उनकी बेटीयों ने ब्रजघाट जाकर गंगा में विसर्जित की हैं। **बच्चों के एक जैसे रखे नाम, बेटों ने जन्मदाता ही मार दिए** गंगाशरण और उनकी पत्नी बिमलेश के चार बच्चों में दो बेटे और दो बेटीयां हैं। बड़े बेटे और बड़ी बेटी का नाम उन्होंने दीपक और दीपिका रखा जबकि छोटे बेटे और छोटी बेटी का नाम उन्होंने ललित और ललिता रखा। सोमवार रात दोनों बेटों ने उन्हें इस दुनिया में लाने वाले माता-पिता को ही मार दिया।

कैसे युवाओं के लिए मोटापा और तनाव बन रहा बड़ा खतरा? एक्सपर्ट्स की राय को न करें नजरअंदाज

नोएडा। मानसिक तनाव बीमारी की ऐसी जड़ है, जिससे किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक आने पर जीवन खराब हो सकता है। हाल के वर्षों में युवाओं में स्ट्रोक, बुजुर्गों में याददाश्त संबंधी समस्याएं और लगातार सिरदर्द के मामलों में वृद्धि हुई है। नोएडा के तमाम विशेषज्ञ इसके पीछे निष्क्रिय जीवनशैली, अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव और बढ़ती आयु को मुख्य कारण मानते हैं। विजय मिश्र दिवस पर बुधवार को विशेषज्ञों ने लोगों को तमाम गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया। **ओपीडी में रोज आते हैं करीब 300 मरीज** सेक्टर-110 स्थित यथार्थ अस्पताल के डा. सत्यन नंदा ने बताया कि वर्तमान दौर में मस्तिष्क एवं तंत्रिका संबंधी बीमारियां के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जागरूकता और समय पर उपचार बेहद आवश्यक है। न्यूरोलाजी



असहनीय सिरदर्द होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं, लगातार भूलना, भ्रम की स्थिति, सही शब्द न मिलना और व्यवहार में बदलाव डिमेंशिया के संकेत हो सकते हैं। नोएडा मैक्स सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के डा. केएम हसन का कहना है कि मानसिक तनाव में जो बीमारियां 60 के बाद आती थीं, वे अब 30 से 45 वर्ष के युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण अत्यधिक तनाव, जंक फूड,

पति ने की दूसरी शादी तो पहली पत्नी ने कर ली आत्महत्या, मुकदमा दर्ज



नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में रहने वाले एक बैंक के अधिकारी ने अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी महिला से शादी कर लिया। इस बात से अहत पहली पत्नी ने मंगलवार की बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतका की बहन की शिकायत पर बुधवार सुबह घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में ले लिया है। थाना सेक्टर -39 के प्रभारी, निरीक्षक डीपी शुक्ला ने बताया कि रीता खन्ना ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह

फरीदाबाद में रहती हैं। उनके अनुसार, उनकी छोटी बहन शैली दुग्गल की शादी प्रशांत शिवाच के साथ हुई थी। वह चंडीगढ़ स्थित एचएसबीसी बैंक में मैनेजर हैं। उनके अनुसार, प्रशांत ने पहली पत्नी के रहते हुए बिना अनुमति के दूसरी शादी कर ली। यह बात जब उनकी बहन शैली दुग्गल को पता चली तो वह मानसिक तनाव में रहने लगी। परिवार के लोगों ने जब प्रशांत से बात की तो उसने कहा कि वह अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह शैली दुग्गल के ऊपर तलाक देने के लिए दबाव डालता रहा।

अल्मोड़ा नगर निगम में 37.15 करोड़ का घाटे का बजट पेश, विकास कार्यों पर हुई लंबी चर्चा

अल्मोड़ा। नगर निगम अल्मोड़ा की बोर्ड बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए 37.15 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया गया। अनुमानित आय 36 करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई, जबकि व्यय इससे अधिक प्रस्तावित होने पर सदन में बजट पर चर्चा हुई। बैठक में अतिक्रमण पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर अजय वर्मा ने की। इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित आठ पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। बैठक में पार्षदों ने 300 कार्यों के प्रस्ताव सदन में रखे। मौके पर 10 दिनों के अंदर आय-व्यय का विवरण देने को कहा। **बोर्ड बैठक में विकास और व्यवस्थाओं पर कई अहम प्रस्तावों पर संधन** मेयर अजय वर्मा ने कहा कि जिन



भी विषयों पर बोर्ड बैठक में चर्चा हुई है उनका समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। नगर की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। नगर को स्वच्छ, सुंदर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पार्षदों को साथ

लेकर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा, सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह, मुकेश भंडारी, प्रशासनिक अधिकारी मुकेश भंडारी, विजय नेगी, शाहिद अली सहित सभी 40 वार्डों के पार्षद

मौजूद थे। **विकास कार्यों को लेकर हंगामा** बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को लेकर हंगामा भी हुआ। पार्षदों ने पूर्व में दिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा की। उन कार्यों के लिए धनराशि अब तक न मिलने

पर नाराजगी देखी गई। उन्होंने वार्डों की मूलभूत समस्याओं के जल्द समाधान की बात भी कही। **बोर्ड बैठक के प्रमुख प्रस्ताव** ● निगम की आय बढ़ाने और व्यय नियंत्रण के लिए नियमावली तैयार करना ● क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों, पुलियों और रेलिंग निर्माण ● स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार और नए विद्युत पोल लगाना ● होटलों के पास सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ● निगम की दुकानों के किरायों की समीक्षा ● पार्किंग संचालन समिति का गठन और नई पार्किंग विकसित करने को सर्वे ● कूड़ा प्रबंधन सुदृढ़ करने और पर्यावरण मित्रों की संख्या बढ़ाना ● आवारा एवं गोवंश के लिए शेल्टर होम का निर्माण **पैदल पुलों का निर्माण**

● जल संस्थान के समन्वय से खराब हैंडपंपों की मरम्मत और पेयजल टैंकर उपलब्ध कराना ● बिना लाइसेंस संचालित व्यवसायों पर कार्रवाई तथा अवैध होर्डिंग हटाना ● पार्कों का सौंदर्यकरण, नामकरण, स्ट्रीट लाइट की नियमित मरम्मत और मेन पावर बॉक्स व्यवस्थित करना ● प्रत्येक पार्षद को पांच लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराना ● पार्षदों को 25000 रुपये का मासिक भत्ता **10 घंटे तक चली बैठक में हुई चर्चा** ● नगर निगम की बोर्ड बैठक मध्याह्न 12 बजे शुरू हुई। जो रात 10 बजे तक चली। नगर निगम में 40 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। जिस कारण बैठक पूरे होने में 10 घंटे लग गए।

वाराणसी नगर निगम का बड़ा अभियान : 100 करोड़ की सरकारी संपत्ति कराई कब्जा मुक्त



वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में नगर निगम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएलडब्ल्यू रोड (ककरमत्ता) स्थित करीब एक बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। बाजार मूल्य के अनुसार इस भूमि की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। नगर निगम ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और वनों से कूड़े से पाट दी गई पोखरी को खुदाई भी शुरू करा दी। महापौर अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर नगर निगम ने इस मामले की प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप करीब 38 वर्ष पुराने भूमि विवाद का पटाक्षेप हो गया। कार्रवाई के दौरान सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में निगम एवं

राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया और तीन जेसीबी मशीनों की मदद से पोखरी की खुदाई शुरू करा दी। मामला मौजा ककरमत्ता (परगना देहात अमानत) स्थित अराजी संख्या-411 से जुड़ा है। वर्ष 1988 में रामनारायण पुत्र स्वर्गीय गज्जन ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य पक्षकारों के विरुद्ध धारा 229(ख) के तहत भूमिधारी अधिकार का दावा किया था। वादी का कहना था कि उनके पूर्वज वर्ष 1356 एवं 1359 फसली से भूमि पर काबिज रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थायी भूमिधर घोषित किया जाए। इस मामले में वर्षों तक अपील और निगरानी याचिकाओं का सिलसिला चलता रहा। वाद संख्या 1987/2025 की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त उपजिलाधिकारी (सदर) राजा सिंह की अदालत ने राजस्व अधिकारियों का गहन परीक्षण किया।

दून शहर में नहीं घुसेंगे कांवड़ियों के वाहन, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस का नया प्लान लागू

देहरादून : कांवड़ यात्रा के दौरान देहरादून शहर को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। कांवड़ियों के वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पांवटा साहिब की ओर से आने वाले कांवड़ वाहनों को धमावाला से ही डायवर्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे के रास्ते आने वाले वाहनों को भी यूप-टर्न कराने की तैयारी है। दरअसल, शहर में स्कूल खुल चुके हैं और छुट्टी के समय जाम लगने की समस्या गंभीर है। इसके साथ ही बारिश के कारण शहर की कई सड़कों की हालत खराब है।



इस कारण भी जाम लग रहा है। ऐसे में यदि कांवड़ यात्रियों के वाहन भी शहर में प्रवेश करते हैं तो जाम की समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसलिए पुलिस ने पहले ही रणनीति तैयार कर ली है।

आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए प्लान तैयार यातायात पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित मार्गों में दिशा सूचक लगाया जाएगा। पांवटा साहिब की ओर से आने वाले

वाहनों को धमावाला से ही वैकल्पिक मार्ग पर भेजा जाएगा। वहीं दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे के जरिए आने वाले कांवड़ वाहनों को भी शहर की सीमा से पहले ही वापस मोड़ा जाएगा, ताकि मुख्य मार्गों पर दबाव कम रहे। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों को अनावश्यक जाम से राहत देना है। विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों, कार्यालय आने-जाने वाले लोगों और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए प्लान तैयार किया गया है।

गौवंश संरक्षण के लिए बने केंद्रीय गौ सेवा कानून, शिक्षा में गौ महत्व हो शामिल



महोबा। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में गौमाता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण में सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को सौंपा गया। लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से देश भर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने समेत गौवंश संरक्षण से जुड़ी प्रमुख मांगों पर केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गयी है। सोमवार को जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में संत समाज के आह्वान पर एकत्रित हुए सनातनियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम गजल भारद्वाज को सौंपते हुए अभियान के संभाव्य प्रभारी निधि त्रिपाठी ने बताया कि गाय की राक्ष माता घोषित करने, देश भर में गौ हत्या

पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौचर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, केंद्रीय गौ सेवा कानून एवं गौ सेवा मंत्रालय का गठन करने, गौ पालकों को सीधे प्रोत्साहन राशि देने, शिक्षा में गौ महत्व को शामिल करने समेत गौ संरक्षण को लेकर अन्य मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उठाया गया है। महंत देवीचरण दास ने बताया कि संत समाज के निर्देश पर यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। पहला चरण 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर संपन्न हुआ था, जबकि दूसरा चरण आज 27 जुलाई को जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। अगला चरण में 27 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर अभियान का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि जब तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता, तब तक हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन सौंपने का क्रम जारी रहेगा।

आगामी छह महीने तक अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दें कार्यकर्ता: केशव मौर्य

प्रयागराज। कार्यकर्ता ये संकल्प लें कि 2047 तक सपा को आने नहीं देंगे और भाजपा को जाने नहीं देंगे। कार्यकर्ता आगामी 06 महीने अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दें 2027 की फतह के लिए। कार्यकर्ताओं की यही मेहनत समाजवादी पार्टी को हमेशा के लिए सैफर्ड भेजने का काम करेगी। उक्त बातें सोमवार को अपने तीन दिवसीय प्रयागराज प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सिकंदर हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से भाजपा आई है

विकास की गंगा बह रही है विकास की आंधी चल रही है। यदि कमल का फूल नहीं खिलता तो गरीबों महिलाओं किसानों युवाओं के लिए जो कल्याणकारी कार्य हुए वे कार्य होते क्या? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में खुद कहा था कि जब दिल्ली से गरीबों के विकास के लिए 1 रुपया भेजा जाता है, तो उसमें से केवल 15 पैसे ही असल लाभार्थियों तक पहुंचते हैं और बाकी के 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। 2017 से पहले प्रयागराज के चकिया चौराहे से लेकर लाल गोपालगंज, हंडिया सहित पूरे गंगापार यमुनापार में गुंडे खुलेआम



लहराते हुए चलते थे। आज गुंडे या तो कहीं और चले गये हैं या अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में कोई हिलाई न बरती जाए। बूथ जीता तो चुनाव जीता के फामूल पर ही चलना है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जनता

दर्शन के माध्यम से स्थानीय जनो की समस्याएं को सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सपा सरकार ने भर्ती आयोग का भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था सिकंदर हाउस में मीडिया से औपचारिक बातचीत में डिप्टी सीएम

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सरकार ने भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था। इन्हें नकल रोकने के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत करते हुए कहा कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हार्ड-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे भविष्य में पेपर लीक को संभावनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके

से ट्रायल चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि संसद में ऐसा सख्त बिल लाया जा रहा है जिससे नकल माफियाओं की रूढ़ कांप जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने सपा से गठबंधन कर बीजेपी को हराने का दावा किया था, डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे थे, अब ओवैसी भी देख रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन वे सब मिलकर भी आ जाएं तो उनका सपना पूरा नहीं होगा और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी।

नाले का पास मिला चालक का शव, सिर के पर मिले चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी



विकासनगर : सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र के लाइन जीवनगढ़ में एक होटल के पास नाले में एक पिकअप चालक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सुनील (35) के रूप में हुई है, जो कालसी कोतवाली क्षेत्र के रिखाड़ गांव का रहने वाला था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोतवाली प्रभारी राजीव रैथाने ने बताया कि मृतक के सिर के पीछे चोट के निशान मिले हैं। शव नाले में मुंह के बल गिरा हुआ था। प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुनील एक पिकअप चालक था और उसका वाहन घटनास्थल के पास ही खड़ा मिला। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक लघु शंका के लिए वाहन से बाहर निकला होगा और इसी दौरान वह नाले में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और वे मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

प्रदेश में 18 वर्षों में 178 से 560 हुए बाघ, एसटीपीएफ में नहीं हुई 81 कर्मियों की भर्ती



देहरादून : राज्य में पिछले 18 वर्षों में बाघों की संख्या तीन गुना से अधिक बढ़कर 560 तक पहुंच गई, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए प्रस्तावित स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) अब तक अस्तित्व में नहीं आ सकी है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए स्वीकृत 81 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। वन विभाग का कहना है कि भर्ती का अधिाचान पहले ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। राज्य में 2008 में बाघों की संख्या 178 थी। इसमें 164 बाघ केवल कार्बेट टाइगर रिजर्व में होने का अनुमान था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वर्ष 2008-2009 में बाघों को शिकारियों से बचाने और सुरक्षा को लेकर एसटीपीएफ बनाने का फैसला किया। इसके तहत कार्बेट, दुधवा और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एसटीपीएफ का गठन होना था। इसके लिए वित्तीय सहायता भी एनटीसीए के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी थी। लेकिन वन महकमा के लचर सिस्टम के चलते करीब 18 साल बीत जाने के बाद भी एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं हो सकी है। इस बीच बाघों की संख्या में खासा इजाफा हो गया। वर्ष-2022 की गणना में बाघों की संख्या राज्य में 560 तक पहुंच गई, इसमें केवल कार्बेट में ही 260 बाघ है। वहीं, फोर्स के गठन की बात करें तो अधिाचान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पिछले वर्ष को भेजा गया था।

17 वन महकमे के मुखिया बदल चुके : 18 साल की अवधि में वन विभाग में एक-दो नहीं बल्कि 17 प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) बदल गए। इसके अलावा कई प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव-मुख्य वन्यजीव प्रिपालक बने, लेकिन फोर्स का गठन नहीं हो सका है। एसटीपीएफ के गठन के लिए वन मुख्यालय से पिछले वर्ष ही अधिाचान भेजा जा चुका है। आयोग की तरफ से कुछ जानकारी मांगी गई थी उसे भी उपलब्ध कराया गया है।

इस महीने अब तक सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक हो चुकी बारिश, भूस्खलन से 56 मार्ग बंद

देहरादून : इस महीने राज्य में सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। राज्य में एक से 26 जुलाई तक सामान्य 354.3 एमएम की तुलना में 372.6 एमएम बरसात हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बागेश्वर जिले में हुई। यहां पर सामान्य से 56 मार्ग बंद हैं। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण 47 मार्ग बंद हैं। पिथौरागढ़ जिले में सबसे अधिक एक राज्यभर में समेत 13 मार्ग बंद है। चमोली में नौ, देहरादून में सात मार्ग बंद है। अल्मोड़ा दो, बागेश्वर पांच, नैनीताल पांच, पौड़ी चार, रुद्रप्रयाग चार , टिहरी एक और ऊधम सिंह नगर में छह सड़क बंद है।

केदारनाथ यात्रा पर मानसून की मार : रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 हजार से नीचे पहुंची



रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा पर इन दिनों मानसून का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रा प्रभावित होने से घाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या घटकर प्रतिदिन एक हजार से भी नीचे पहुंचने लगी है। यात्रियों की संख्या में आई कमी का सीधा असर केदारघाटी के स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय और अन्य पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभाग मार्ग को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में यात्रा बाधित होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक गिरने से आगमन जोखिम भरा बना हुआ है। केदारघाटी में देर रात और तड़के होने वाली भारी बारिश के बावजूद वाहनों का संचालन लगातार जारी रहने से स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने चिंता जताई है। व्यापारियों ने मानसून के दौरान रात के समय पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में सुरक्षा के भेदनजर एक निश्चित समय के बाद वाहनों के आगमन पर रोक लगाई जानी चाहिए। श्री केदारनाथ होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने कहा कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए रात्रि में एक निर्धारित समय के बाद केदारनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

11 साल पुरानी खेल नीति में होंगे बड़े बदलाव, विधा के तौर पर शामिल होगा योगासन, क्या है नई व्यवस्था

ग्रेडेशन नीति में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। अब केवल मान्यता प्राप्त और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा।

चंडीगढ़ : हरियाणा की 11 साल पुरानी खेल नीति अब पूरी तरह नए स्वरूप में नजर आएगी। सरकार ने 2015 की संशोधित खेल नीति का नया खाका लगभग तैयार कर लिया है। इसमें केवल पुरस्कार राशि बढ़ाने की बजाय खिलाड़ियों को बचपन से तैयार करने, ग्रेडेशन व्यवस्था बदलने और सरकारी नौकरियों के नियमों में संशोधन जैसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।

सबसे बड़ा बदलाव: सबसे बड़ा बदलाव खेल नीति से योग शब्द हटाकर योगासन को खेल विधा के रूप में शामिल करना माना जा रहा है। इससे योगासन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी

अन्य खेलों की तरह नीति का लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रेडेशन नीति में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। अब केवल मान्यता प्राप्त और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा। डोपिंग के मामलों में पहले से अधिक सख्ती होगी। पैरा खिलाड़ियों को मुख्यधारा के खिलाड़ियों के समान अवसर देने का प्रस्ताव है। खेल संघों की पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित चुनाव भी नई नीति का अहम हिस्सा होंगे। सरकार विश्वविद्यालयों के स्पोर्ट्स विभाग



का नाम बदलकर स्पोर्ट्स एवं योगासन विभाग करने की तैयारी में है। साथ ही योगासन प्रशिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी की जाएंगी। खिलाड़ियों की पूरी

प्रोफाइल, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और उपलब्धियों का रिकॉर्ड अब खेले हरियाणा एप पर डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। इससे प्रतिभा की निगरानी और योजनाओं का लाभ

देने में पारदर्शिता आएगी।

इनाम नहीं निवेश पर फोकस

नई नीति का पूरा फोकस इनाम नहीं निवेश पर रखा गया है। सरकार की योजना 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें वैज्ञानिक, आधुनिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण देने की है, ताकि भविष्य के ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की मजबूत शृंखला तैयार हो सके। नई नीति का उद्देश्य केवल पदक जीतने वालों को सम्मानित करना नहीं बल्कि गांव-गांव से प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इसी सोच के तहत खेल नर्सरी, उत्कृष्टता केंद्र और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।

ये होंगे बड़े बदलाव

- योग की जगह योगासन को खेल विधा के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 8-10 वर्ष की उम्र से प्रतिभाओं की पहचान कर लंबी अवधि का प्रशिक्षण मिलेगा।
- ग्रेडेशन प्रणाली को प्रदर्शन और मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं से जोड़ा जाएगा।
- सरकारी नौकरी के नियम अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होंगे।
- खेलो हरियाणा एप से खिलाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा।

पुलिसकर्मों पर हमला: नशा करने से रोकने पर घर में घुसे 15-20 युवक, तोड़फोड़ के बाद की मारपीट



अमृतसर : अमृतसर के फतेहपुर क्षेत्र की जीवन सिंह कॉलोनी में रविवार को 15 से 20 युवकों ने एक पुलिस कर्मी के घर में घुसकर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ भी की और पुलिस कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पुलिस कर्मी को उपचार के लिए सविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घायल पुलिस कर्मी की पत्नी मनप्रीत कौर ने बताया कि कुछ समय पहले उनके पति ने इलाके में नशा करने वाले कुछ युवकों को नशा करने से रोका था और पुलिस में पकड़वा देने की बात कही थी। इसी

रंजिश के चलते आरोपियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी, सामान को नुकसान पहुंचाया और उनके पति पर बेरहमी से हमला किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

अमृतसर का आरटीओ दफतर होगा शिफ्ट, जर्जर भवन से मिलेगी राहत; मंजूरी का इंतजार

अमृतसर आरटीओ कार्यालय जर्जर भवन से स्थानांतरित होगा। नया स्थान बस अड्डे के पास रेड क्रॉस भवन प्रस्तावित। ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक से दूरी बढ़ने की चिंता।

अमृतसर। अमृतसर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का पता करीब 16 वर्ष बाद एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौजूदा जर्जर भवन से राहत दिलाने के लिए विभाग ने कार्यालय को बस अड्डे के समीप स्थित रेडक्रास भवन परिसर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कार्यालय को नई जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले से कर्मचारियों और आम लोगों को असुविधा भवन से राहत मिलेगी, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक और मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालय से दूरी बढ़ने के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अब केवल मुख्यालय की स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही विभाग बिना देरी किए कार्यालय को नई जगह स्थानांतरित कर देगा।



उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को टेलर रोड से ग्वालमंडी स्थानांतरित किया गया था। अब करीब 16 वर्ष बाद इसे फिर से नए पते पर ले जाने की तैयारी चल रही है।

तीन किलोमीटर की बढ़ेगी अतिरिक्त दूरी

मौजूदा समय में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक और मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालय की दूरी करीब एक से डेढ़

किलोमीटर है। किसी भी दस्तावेज की जांच, वाहन पासिंग या अन्य औपचारिकताओं के लिए आवेदक आसानी से कुछ मिनटों में दोनों कार्यालयों के बीच पहुंच जाते हैं। नई जगह कार्यालय शिफ्ट होने के बाद यह दूरी बढ़कर करीब तीन किलोमीटर हो जाएगी। इससे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, वाहन पासिंग और अन्य परिवहन संबंधी कार्य करवाने आने वाले लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी

पड़ेगी। समय के साथ ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। बस अड्डे के आसपास अक्सर यातायात का दबाव बना रहता है। ऐसे में लोगों को दस्तावेजी कार्यों के लिए आने-जाने में अधिक समय लग सकता है। यही परेशानी विभागीय कर्मचारियों के सामने भी आएगी, जिन्हें दिनभर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालय के बीच कई बार आना-जाना पड़ सकता है।

दुकानदारों की भी बढ़ी चिंता

ग्वालमंडी चौक के आसपास वर्षों से ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य परिवहन संबंधी दस्तावेज तैयार करने का कार्य करने वाले दुकानदारों की चिंता भी बढ़ गई है। उनका मानना है कि कार्यालय स्थानांतरित होने के बाद ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है, जिससे उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा।

बाढ़ से फसल खराब हुई: पांच लाख का कर्ज था, बैंक प्रबंधन ने दी जमीन कुर्की की चेतावनी



ममदोट (फिरोजपुर) : फिरोजपुर जिले के ममदोट क्षेत्र में बैंक कर्ज और जमीन कुर्की की चेतावनी से परेशान एक किसान ने सल्फास निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव हरगोबिंदपुरा निवासी बगीचा सिंह के रूप में हुई है। किसान की मौत के बाद परिजन ने बैंक प्रबंधन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के बेटे गुप्ते सिंह ने बताया कि उनके पिता पर पंजाब नेशनल बैंक का करीब पांच लाख

रुपये का कर्ज था। 16 जुलाई को वह बैंक गए थे। वहां से लौटने के बाद वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे। उन्होंने परिवार को बताया था कि बैंक अधिकारियों ने कर्ज न चुकाने पर जमीन कुर्की करने की चेतावनी दी है। इसी तनाव के चलते उन्होंने सल्फास निगल लिया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन के अनुसार बगीचा सिंह अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।

पंजाब पुलिस के शिकंजे में आया गैंगस्टर बिल्ला, इंडोनेशिया से डिपोर्ट; चार हत्या समेत कई संगीन मामलों में शामिल

► गैंगस्टर ज़ोबन बिल्ला इंडोनेशिया से भारत डिपोर्ट।
► डिपोर्ट के छह महीने तक चली अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई।
► विदेश में रहते हुए भी अपने नेटवर्क के संपर्क में था।



हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार रविवार शाम एंजीटीएफ की टीम गैंगस्टर को लेकर एयरपोर्ट पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। बाहर निकलते ही अमृतसर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान गैंगस्टर के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे अमृतसर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर ज़ोबन

बिल्ला लंबे समय से विदेश में रहकर गिरफ्तारी से बच रहा था। उसके खिलाफ पंजाब में चार हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि विदेश में रहते हुए भी वह अपने नेटवर्क के संपर्क में था।

तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट से मिला सुराग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गैंगस्टर को भारत लाने के लिए

विशेष अभियान चलाया गया। करीब 6 माह तक एंजीटीएफ, ऑपफटीईसी पंजाब और केंद्रीय एजेंसियों ने तकनीकी निगरानी, खुफिया इनपुट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाकर कार्रवाई की। इसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया।

विदेशी संपर्कों और गैंग नेटवर्क की होगी पड़ताल

अब जांच का फोकस गैंगस्टर के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और पंजाब में सक्रिय उसके नेटवर्क पर रहेगा। पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि विदेश में रहते हुए वह किन लोगों के संपर्क में था, गैंग का संचालन कैसे कर रहा था और किन मामलों में उसकी भूमिका रही है। इसके अलावा उसके आर्थिक स्रोतों और अन्य फरार साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। पंजाब पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल: बिजली संकट गहराया, निजी इलेक्ट्रिशियन बुलाकर फॉल्ट सही करवा रहे लोग

होशियारपुर के फतेहगढ़ स्थित रामचर[]न्वलेव में सामने आया। यहां एक निजी इलेक्ट्रिशियन द्वारा बिजली व्यवस्था ठीक करने के प्रयास के बाद करीब 50 घरों की बिजली पूरी तरह बंद हो गई, जबकि 15 से 20 घरों में 440 वोल्ट की सप्लाई पहुंच गई।

होशियारपुर : पंजाब में नियमित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। होशियारपुर जिले के लोगों को फिलहाल बिजली संकट से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली लाइनों की मरम्मत और फॉल्ट ठीक करने का अधिकतर काम करने वाले ठेका एवं आउटसोर्स कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार रिपेयर कार्य में लगे लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी आउटसोर्स श्रेणी से संबंधित हैं और उनकी हड़ताल अभी जारी है। जिले के अनेक क्षेत्रों में पिछले 18 से 20 घंटे से बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। कहीं फॉल्ट के कारण

बिजली पूरी तरह बंद रही तो कहीं लोगों को बेहद कम वोल्टेज का सामना करना पड़ा। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों को पेयजल, घरेलू कार्यों और कारोबार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली बहाल न होने पर कई इलाकों में लोगों ने अपने स्तर पर निजी इलेक्ट्रिशियन बुलाकर फॉल्ट ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन कई स्थानों पर इसका उल्टा असर देखने को मिला। गलत तरीके से मरम्मत किए जाने के कारण कहीं बिजली पूरी तरह बंद हो गई तो कहीं 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट की सप्लाई पहुंचने लगी, जिससे लोगों के घरेलू



उपकरण जल गए। ऐसा ही मामला होशियारपुर के फतेहगढ़ स्थित रामचरण एंक्लेव में सामने आया। यहां एक निजी इलेक्ट्रिशियन द्वारा बिजली

व्यवस्था ठीक करने के प्रयास के बाद करीब 50 घरों की बिजली पूरी तरह बंद हो गई, जबकि 15 से 20 घरों में 440 वोल्ट की सप्लाई पहुंच गई।

इससे अनेक परिवारों के एलडी टीवी, फंखे, लाइटें, मॉडेम, राउटर, सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित लोगों ने विभाग से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। नियमित कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने से कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन इसका असर सीमित रहेगा।

नियमित कर्मचारी अब दोबारा पावर सब-स्टेशनों का संचालन संभालेंगे, जबकि हड़ताल के दौरान सब-स्टेशनों पर तैनात किए गए एसडीओ की हड़ताल समाप्त नहीं होगी, तब तक जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौटने में समय लग सकता है।

में तेजी ला सकें। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर औपचारिक से निजी इलेक्ट्रिशियन और तकनीकी कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है ताकि लॉबत फॉल्ट जल्द दूर किए जा सकें और आम लोगों को राहत मिल सके। हालांकि विभाग को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य होने लगेगी, लेकिन जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त नहीं होती, तब तक जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौटने में समय लग सकता है।

सार संक्षेप

पंजाब के संगरूर में भाजपा के जिला कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला, इलाके में सनसनी



संगरूर। संगरूर के उपली रोड पर स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला कार्यालय को सोमवार देर रात असाમાजिक तत्वों ने कथित तौर पर पेट्रोल बंप से निशाना बनाया। घटना का पता सोमवार सुबह कार्यालय खोले जाने के बाद चला। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी संगरूर दलबीर सिंह, सीआईए इंचार्ज संदीप सिंह तथा थाना सिटी संगरूर के एसएचओ सुखदेव सिंह पुलिस टीम के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाई। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है तथा हमले के पीछे शामिल लोगों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना में किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि, भाजपा कार्यालय पर हुए हमले को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष है। भाजपा के जिला प्रधान मनिंदर सिंह कपियाल और पूर्व जिला प्रधान संदीप सिंह देवल ने घटना की कड़ी निंदा की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व पहले थानों और अन्य संस्थानों को निशाना बना रहे थे और अब राजनीतिक दलों के कार्यालय भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने सरकार से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने बताया कि घटना की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह दिल्ली को भी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

बरनाला की घटना के विरोध में पंजाब बंद: बाजार-परिवहन प्रभावित, जालंधर के स्कूलों में छुट्टी; पुलिस तैनात



जालंधर : बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में वाल्मीकि समाज ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। इसका असर जालंधर में भी दिखाई दिया। बंद को देखते हुए एमजीएन स्कूल, सेठ हुसम चंद स्कूल, इमोसेंट हाई स्कूल और शिव ज्योति स्कूल ने छुट्टी घोषित कर दी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कई स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। बाजारों और परिवहन पर भी असर देखने को मिला। वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों ने आम जनता, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और सभी वर्गों से बंद का समर्थन करने और उनके आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बंद के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान और परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, अब तक किसी प्रमुख व्यापारिक संगठन या एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से बंद के समर्थन की पुष्टि नहीं की है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर पुलिस फोर्स देना की गई है ताकि लोगों को आवाजही परेशानी ना हो।

मक्का किसानों के लिए एचएयू के वैज्ञानिकों की बड़ी सलाह, फाल आर्मीवर्म और पत्ती अंगमारी रोग से ऐसे बचाएं फसल

हिसार। मक्का की फसल इस समय बढ़वार के अहम दौर में है। ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही किसानों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के कृषि वैज्ञानिकों की विशेष एडवाइजरी प्रकाशित की गई है। इसमें किसानों को 31 जुलाई के दौरान मक्का की फसल की देखभाल, रोग एवं कीट नियंत्रण तथा बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सलाह दी गई है।

अमृतसर की युवती की टोरंटो में हत्या: शादी का दबाव बना रहा था आरोपी, इनकार करने पर मारी गोली



हलवारा : कनाडा के टोरंटो शहर में अमृतसर निवासी 26 वर्षीय नवनीत कौर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात 24 जुलाई को हुई, जिसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने आरोपी शरनजीत सिंह (37) को गिरफ्तार कर लिया।

► नवनीत कौर उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गई थीं। आरोपी शरनजीत सिंह लंबे समय से नवनीत को परेशान कर रहा था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था।

शुरूआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से नवनीत को परेशान कर रहा था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद वह लगातार युवती का पीछा करता था और विवाह के लिए दबाव डाल रहा था। टोरंटो पुलिस के अनुसार, हंबरवुड बुलेवार्ड और रेक्सडेल बुलेवार्ड क्षेत्र में नवनीत कौर और शरनजीत सिंह के बीच बातचीत हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने पिस्तौल निकालकर नवनीत पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल

नवनीत को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग निकला था। पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाकर शरनजीत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शरनजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसे शनिवार को ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया गया। नवनीत कौर उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गई थीं। परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है।

सक्षिप्त समाचार

लोकतंत्र में जवाबदेही को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता : शशि थरूर

नई दिल्ली, एजेंसी। शनिवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा छात्रों की सभी मांगों को भी मान लिया गया। इसके बाद कोकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस मामले पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। थरूर ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी तब आया है जब संसद मार्च करने वाले छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से हमला किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर शशि थरूर ने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात की स्वीकारोक्ति है कि लोकतंत्र में जवाबदेही को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। यह इस्तीफा देश भर में दृढ़तापूर्वक, शांतिपूर्ण और प्रतिबद्ध आवाज उठा रहे छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों के हफ्तों लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद आया है। शशि थरूर ने लिखा कि यह तब आया है जबकि असंख्य युवा भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार के कारण पुलिस की बर्बरता का अनुचित रूप से सामना करना पड़ा। इसकी चिंता हर नागरिक को होनी चाहिए, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जवाबदेही एक इस्तीफे से खत्म नहीं होती।

दीपके बिहार आकर सम्राट चौधरी की सरकार उखाड़ फेंकिए तेज प्रताप यादव ने दिया न्योता

पटना, एजेंसी। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सुभाष चौधरी की सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद चौकाने वाला और आक्रामक पोस्ट साझा कर विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी है. तेज प्रताप यादव ने ‘काँकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके से तुरंत बिहार आने की विशेष अपील की है. उन्होंने कहा कि सुबे के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए अब एक बड़े और कड़े जनदोलन की सख्त जरूरत है. तेज प्रताप ने अभिजीत दीपके से आग्रह किया है कि वे बिहार की धरती पर कदम रखें।

कर्नाटक : सीएम शिवकुमार बोले- प्राइवेट स्कूल मालिकों को सरकारी स्कूल गौद लेने चाहिए

चित्रदुर्ग, एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट से अपील की है कि वे अच्छी शिक्षा देने के लिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों को गौद लें. शनिवार को चित्रदुर्ग जिले में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि इसका फ़क़सद गांव के स्कूलों को इंग्रारस्ट्रक्चर और क्वालिटी दोनों में बंगलुरु के स्कूलों के स्तर तक ले जाना है. उन्होंने रुका कि उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. उन्होंने कहा कि जो लोग बड़े प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वे उद्यमियों के अलावा कुछ नहीं हैं और ऐसे उद्यमियों को सीएसआर अवसर पर पैसा खर्च करना जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘इसलिए मैंने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि उन्हें सीआरआर पॉलिसी के अनुसार पैसा खर्च करना चाहिए. एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार अगले हफ़ते होगा. कैबिनेट का विस्तार 21 जुलाई को होना था, लेकिन लोकसभा नेता राहुल गांधी के नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण पार्टी हाईकमान इसे अंतिम मंजूरी नहीं दे सका. उन्होंने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के निलंबन के मामले में भी भाजपा पर पलटवार करने की कोशिश की।

1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रूप से नाम जुड़वाने पर FIR दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेंशंस कोर्ट ने शनिवार को 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रूप से नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने अब इस मामले में 13 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया. याचिका कवील विकास त्रिपाठी ने दायर किया है. विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के खारिज करने के आदेश को सेंशंस कोर्ट में चुनौती दी है. 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था।

करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ: राजनाथ बोले, ‘देश की सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार’

श्रीनगर, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन बार-बार नाकाम होने के बावजूद प्रॉक्सि वॉर और घुसपैठ जैसी ‘नापाक चालें’ अपनाते रहते हैं. रविवार को संसद बल करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाएगी. यह दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है. 27वें करगिल विजय दिवस की एक शाम पहले द्रास में एक यादगार कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए, सिंह ने 1999 के करगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत, देशभक्ति और बलिदान सेना और देश दोनों को प्रेरणा देते रहते हैं. सिंह ने कहा, ‘देश होनी के इरादे बदले नहीं हैं और वह प्रॉक्सि वॉर (परोक्ष युद्ध) और घुसपैठ जैसे खतरनाक तरीके अपना रहा है,

फिर भी भारतीय रक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ‘ उन्होंने कहा कि करगिल लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, वह आज भी हिम्मत और देश के गर्व की निशानी है. सेना पर भरोसा जताते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा उसके सैनिकों के पक्के इरादे पर टिकी है. उन्होंने कहा, ‘जब तक देश के बहादुर सैनिकों की देशभक्ति और इरादा पक्का है, तब तक कोई भी भारत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता. उनकी हिम्मत हर नागरिक को बिना किसी डर के अपने सपने पूरे करने और उन्हें पूरा करने में मदद करती है.’

सैनिकों के साथ पारंपरिक बड़ाखाना खाने पर बातचीत के दौरान, सिंह ने कहा कि, देश को करगिल में मिली जीत का जश्न मनाना चाहिए और साथ ही बदलती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भी अलर्ट रहना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘करगिल की जीत को याद करके हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति होगी जब्त: सीएम योगी आदित्यनाथ

फतेहपुर , एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक वाला नकल माफिया इन्हीं दलों की विरासत है, जिसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल दो ही जगह हैं- जेल या जहनन्मु।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ ऐसा सख्त कानून ला रही है, जिसके तहत दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा और १10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहपुर सदर और अयाह-शाह विधानसभा क्षेत्रों के लिए १489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही ‘जय श्रीराम’, ‘मोदी-योगी जिंदाबाद’ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विभिन्न स्टॉल्स पर लोगों से बातचीत की तथा बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, उन्हें तिलक लगाया और खिलौने भेंट किए।

कोई नहीं रोक सकता नकल माफिया को मिट्टी में मिलने से : अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकारमय जीवन खड़ा



किया, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले तीन दिनों में बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। ये नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता इन माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया कांग्रेस व सपा की विरासत हैं। इन्होंने ही माफिया को पाला-पोसा और संरक्षण दिया था।

पेपर लीक पर पीएम मोदी जी ने उठाए कड़े कदम : मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा समय सीमा के भीतर कराई गई, ताकि छात्रों का पूरा वर्ष खराब न हो, और निर्धारित समय सीमा में उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। कुछ माफिया ने प्रश्नपत्र लीक कराया था, उनकी गिरफ्तारी हुई और नेशनल टैरिंजर एजेंसी (एनटीए) के तमाम अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। कुछ लोगों की

गिरफ्तारी हुई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें सजा मिलेगी। ये छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर पीएम मोदी जी द्वारा उठाए गए कड़े कदम हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी जी ने छात्रों व युवाओं के लिए पिछले 12 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना और प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना के माध्यम से भारत के नौजवानों में आशा की नई किरण जागृत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर नौजवानों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दिया। आज भारत के नौजवानों को दुनिया में सम्मान मिलता है। मोदी जी ने युवाओं को एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरियां दीं और गत 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर की देकर उनके जीवन को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। आज जब युवाओं के मन में कुछ कसक थी, तब पीएम स्वयं सामने आए, युवाओं के साथ संवाद किया और संसद में सख्त कानून लाने के लिए कैबिनेट से नए अधिनियम के मसौदे को पारित कराया, यह अभिनंदनीय है।

माफिया पर नकेल कसी और दूँ 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां : मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं युवाओं के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिसने छात्रों व युवाओं के भविष्य के

साथ खिलवाड़ किया, उस माफिया के लिए दो ही जगह होंगी- जेल या जहननु। माफिया के बाप-दादा की कमाई गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। हमने माफियाओं पर सख्ती से लगाम कसी है। ऐसा न किया होता तो हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते।

भाजपा की जमीन पर था पूर्व सपा विधायक का कब्जा : सीएम ने कहा कि सपा के एजेंडे में विकास कभी नहीं था और न है। सपा के लोग अब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके, पट्टे और अवैध जमीनों पर कब्जे का उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए वे हताश-निराश बैठे हुए हैं। पहले वे किसी भी खाली जमीन या प्लॉट पर कब्जा कर लेते थे। भाजपा ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली थी। जब कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो पता चला कि उस जमीन पर भी सपा के एक पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा था। कल हमने बुलडोजर भेजकर उस कब्जे को हटवाया है। यही इनका धंधा था। खेत बोता कोई और था, लेकिन फसल काटने ये लोग पहुंच जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गरीब को मुफ्त राशन व आवास की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत १5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा पहुंचा है।

भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मृत्यु सोने के आभूषणों से सजे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

पुरी, एजेंसी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की ‘सुना बेषा’ देखने के लिए लाखों भक्त पुरी के ग्रैंड रोड पर इकट्ठा हुए हैं। दर्शन शनिवार को देर रात तक जारी रहेंगे. भगवान के सोने के कपड़े (सुना बेषा) को ‘बड़ा तथै बेषा’ भी कहा जाता है. परंपरा के अनुसार, बहुड़ा यात्रा (एकादशी) के आने दिन, श्रीमंदिर के सिंहराार के सामने ‘रथरुद्र चतुर्धर्मति’ (रथों पर सवार त्रिभुति) को सोने के कपड़े पहनाए जाते हैं. दिन में पहले, रथ पर महाप्रभु की धूप-बत्ती की रस्म की गई. फिर पलिया भंडारी मेकप, पलिया खुंटिया के सेवक मजिस्ट्रेट, पुलिस और मंदिर के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के खजाने से सोने के गहने लाए. शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ को सोने के गहनों से सजाया गया. पौराणिक कथा के मुताबिक, रथ यात्रा के पहले दिन,



उस समय के राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु को यह दुर्लभ सोने का कपड़ा पहनाया था. बाद में, दक्षिणात्य की जीत के बाद, गजपति कपिलेंद्र देव 16 हाथी गाड़ियों में भरकर सोने के गहने लाए और उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिया. उस समय, राजा कपिलेंद्र देव ने तथैकरण की सलाह पर बहुदा एकादशी पर महाप्रभु का सुनहरा पहनावा किया था. चूंकि महाप्रभु का सुनहरा पहनावा सिंहासन पर किया गया था, इसलिए दूसरे वर्ग के भक्त यह नजारा देखने से वर्जित रह गए थे.

ओडिशा पुलिस शनिवार रात से पुरी-भुवनेश्वर रोड पर हर एक घंटे में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रही है. पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम पुरी से जारी अपनी नई एडवाइजरी में कहा है कि भुवनेश्वर की तरफ से पुरी की तरफ गाड़ियों का बहुत ज्यादा आना-जाना है, जिससे रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लग गया है. इसमें कहा गया है कि पुरी शहर के पास एंटी पॉइंट, माल्टीपटपुर पर इंतजार का समय अब बढ़कर लगभग 150 मिनिट हो गया है और दिन चढ़ने के साथ इसके और बढ़ने की संभावना है. पुलिस ने आने-जाने वालों से कहा है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और आगे की ट्रैफिक एडवाइजरी से अपडेट रहें. पुलिस ने लोगों से भी कहा है कि वे इस त्योहार के समय में ट्रैफिक को आसान बनाने और सभी भक्तों की सुरक्षा के लिए इट्यूटी पर मौजूद लोगों के साथ सहयोग करें।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर विवाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माफी मांगने को कहा

श्रीनगर, एजेंसी। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगा है कि उन्होंने आतंकवाद का हवाला देते हुए कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बल प्रयोग या हिंसा को एक तरह से सही ठहराया है. इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कथित तौर पर कहा था कि कश्मीर में आतंकवाद और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की स्थिति होने के कारण वहां प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कुछ हद तक समझ में आता है. अपनी बेटी इलतजा मुफ्ती के साथ नई दिल्ली में जंतर-मंतर गई मुफ्ती ने काँकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के दौरान यह बात कही. हालांकि, उसी वीडियो क्लिप में मुफ्ती बिना हथियार वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की बुराई करती दिख रही हैं. मुफ्ती ने कहा, ‘सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि दंगाई भी स्टूडेंट्स को पीटने में उनकी मदद कर रहे थे. हमने कश्मीर में कई सालों से यह देखा है, लेकिन वहां आतंकवाद है, जहां एक तरफ सुरक्षा बल हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी हैं. इसलिए, यह कुछ हद तक समझ में आता है. लेकिन ये छत्र बिना हथियार के, अहिंसक थे और उनके पास कोई पत्थर नहीं था. फिर भी, दिल्ली पुलिस और दंगाई उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर तनवीर ने कहा कि कश्मीरी भी देश के नागरिक हैं, लेकिन मुफ्ती ने कश्मीर में हर प्रदर्शनकारियों को ‘मिलिटेंट’ कहा है. उन्होंने कहा, ‘कश्मीरी छात्र या प्रदर्शनकारी का दर्द, इज्जत और हक किसी भी दूसरे भारतीय से कम नहीं हैं. दुख की बात है कि पीड़पी अक्सर कश्मीरियों के साथ खुलकर खड़ी होने के बजाय उनके दुख को सही ठहराती रही है. यह नेतृत्व नहीं, बल्कि पद छोड़ना है. ‘

यह तब हुआ जब मुफ्ती और दूसरी जम्मू कश्मीर पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन में शामिल होने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण को ठुकरा दिया था. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस प्रदर्शन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लीड किया.

एनसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन पर चुप रहने का आरोप लगाया, जबकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हक के लिए लड़ रही थी. तनवीर ने कहा, ‘यह दुख की बात है कि यहां बैठे कई राजनीतिक नेता अपने घरों से टवीट कर रहे थे।

मुलायम सिंह यादव का सपना था सैफई ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, भाजपा ने पूरा किया : मुख्यमंत्री

योगेश कुमार

इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सैफई मेडिकल संस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सैफई ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन पांच वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव उसे आगे नहीं बढ़ा सके। भाजपा सरकार ने 490 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक पूरा कराया, जबकि 232 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड का गायनी ब्लॉक भी बनवाया, जिससे संस्थान तेजी से विकसित हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इटावा, जसवंतनगर एवं भरथना विधानसभा क्षेत्र में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण



पत्र भी वितरित किए। सपा पर तोखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन उसके लिए इच्छाशक्ति और समय चाहिए था। बबुआ तो दोपहर 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम चले जाते थे और 7 बजे महफिल जम जाती थी। जनता और विकास के लिए समय कहाँ था। यही कारण था कि प्रदेश और

इटावा लंबे समय तक पहचान के संकट से जूझते रहे। पहले इटावा के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब प्रदेश और देश में उन्हें वही सम्मान मिलता है जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इटावा की पहचान बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2017 से पहले इटावा सहित पूरे प्रदेश में

अपराध, भय और अराजकता का माहौल था। लोग इस क्षेत्र से गुजरने तक से डरते थे। उस समय प्रदेश में निवेश नहीं आता था क्योंकि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अपराध और अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और संगठित अपराध तथा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। भाजपा ने जो कहा, उसे करके

दिखाया। पहले प्रदेश के हर जिले में माफिया सक्रिय थे और उत्तर प्रदेश की पहचान दंगा, कर्फ्यू, अराजकता और संगठित अपराध से जुड़ गई थी। इससे युवाओं, किसानों, कारीगरों और आम नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। अब वही प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट- वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट- वन क्यूजन की पहचान बनी है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है, न कर्फ्यू, न उपद्रव और न ही संगठित अपराध का बोलबाला है। प्रदेश अब उत्सव, विकास और निवेश का केंद्र बन गया है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहाँ भी जाता है, उसे सम्मान मिलता है और प्रदेश की नई पहचान देशभर में स्थापित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं ने

जमीन पर काम करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। उनके अनुसार नौकरी से लेकर विकास योजनाओं तक पर एक सिंडिकेट का कब्जा हो गया था, जिससे युवाओं, किसानों और श्रमिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। इसी कारण उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक बीमारू राज्य कहा जाता रहा। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। पहले विकास के लिए धन तो उपलब्ध था, लेकिन भ्रष्टाचार और बिचौलियों के कारण सड़क, पुल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य विकास परियोजनाएँ पूरी नहीं हो पाती थीं। गरीबों के राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ भी बीच में ही हड़प लिया जाता था। अब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुँच रहा है।



रायपुर। राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि मनुष्य, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के बीच संतुलन बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्रदूषण आज गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें अभी से जल संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। राज्यपाल डेका ने आज रविवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरविद्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधनहूके लिए आयोजित राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने अभियान में शामिल ब्रह्माकुमारी

बहनों एवं भाइयों को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 26 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक रायपुर से जबलपुर की यात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता का संदेश देगा। राज्यपाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान की यह पहल केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जन-जागृति का अभियान है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डेका ने कहा कि प्रकृति हमारी माँ के समान है और उसका संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है।

बोह क्षेत्र के बेघर परिवारों को गृह निर्माण और अन्य सामान के लिए 8.50 लाख की आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने रविवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बदल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया तथा वहां ठहराए गए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कपड़े, बर्तन एवं अन्य आवश्यक घरेलू सामान की खरीद के लिए एक लाख की सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों के पास रहने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकार आवश्यकतानुसार सरकारी भूमि भी उपलब्ध करावाएगी। ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन परिवारों की गाय या भैंस आपदा में मर गई है, उन्हें 55 हजार प्रति पशु तथा जिनकी बकरियाँ मरी हैं, उन्हें 15 हजार प्रति बकरी की सहायता राशि



दी जाएगी। जिन घरों में बाढ़ या आपदा के पानी से नुकसान हुआ है, उन्हें एक लाख की राहत प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए नुकसान के आधार पर 50 हजार से एक लाख तक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें 5 हजार प्रति कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जिन परिवारों को अस्थायी रूप से किराए के मकान में रहना पड़ेगा, उन्हें 5 हजार प्रतिमाह किराया सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों को छह माह का राशन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिडकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 की आपदा के दौरान प्रदेश में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे और लगभग 500 बहुमूल्य जीवन गंवाए थे। प्रदेश सरकार ने 75 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया था, जिसकी सराहना नीति आयोग और विश्व क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंचा है।

दो वर्षों में एक लाख नियमित शासकीय पदों पर होगी भर्ती: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी दो वर्षों में प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख नियमित शासकीय पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा की है। पदोन्नति से रित्त हुए पदों को चरणबद्ध रूप से भरते हुए प्रत्येक विभाग का वार्षिक बजट कैलेंडर तैयार किया जाएगा तथा भर्ती एजेंसियों के माध्यम से समयबद्ध चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप समान अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, निष्पक्ष

और समयबद्ध भर्ती व्यवस्था ही युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने का आधार है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, तकनीक आधारित एवं अस्थायी हितैषी बनाने के लिए व्यापक सुधारों का निर्णय लिया है। इन सुधारों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को स्पष्ट दिशा मिलेगी तथा भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और समयबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये व्यापक सुधार प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष अवसर प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगे।



मुख्यमंत्री नायब सेनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत की प्रगति आध्यात्मिक आधार पर भी चलती है। लगातार यह ऐसे ही चलती है और बढ़ती रहेगी।

कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि दो करोड़ रुपये होगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर रविवार को गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर कारगिल के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि कारगिल विजय भारतीय



सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 18 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में

भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता का परिचय देकर दुश्मन को परास्त किया और भारत की सैन्य शक्ति का परिचय कराया।

मगवान बुद्ध का शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत: नीतीश कुमार



पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को वैशाली गढ़ पहुंचे, जहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस यात्रा में विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सराफ भी नीतीश कुमार के साथ थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना कर राज्यवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की तथा विश्वस्तरीय बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप का भी अवलोकन किया।

साथ ही उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों एवं उनकी स्मृतियों का दर्शन कर संग्रहालय में संरक्षित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी भी प्राप्त की। नीतीश कुमार के आगमन से कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं से आत्मीय संवाद किया और उनका कुशलक्षेम जाना। मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है तथा उनकी शिक्षाएँ हमें सेवा, सद्भाव और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि वैशाली की यह पावन धरती भगवान बुद्ध की अमूल्य विरासत की साक्षी रही है और इस धरोहर का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का वैशाली की धरती से हमेशा एक विशेष जुड़ाव रहा है।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी महिलाओं के साथ सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के सांगानेर में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात देश के करोड़ों नागरिकों को सकारात्मक सोच, राष्ट्र निर्माण और जनभागीदारी से जोड़ने का माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनका पराक्रम प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप रक्षा उत्पादन, स्वदेशी तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की निरंतर बढ़ती

क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों और तकनीक पर दुनिया का विश्वास मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, वोकल फॉर लोकल, खादी, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों तथा जनभागीदारी आधारित अभियानों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताते हुए नागरिकों से इन्हें जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। उन्होंने विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल, युवाओं की उपलब्धियों और स्थानीय नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति, सकारात्मक सोच और सक्रिय सहभागिता ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्येक माह देश के दूर-



दराज क्षेत्रों में समाज, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामान्य नागरिकों की प्रेरक कहानियों को पूरे देश के सामने लाते हैं। इससे सेवा, समर्पण और नवाचार की संस्कृति को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के

सशक्तीकरण, देश के महापुरुषों के आदर्शों, युवाओं की भूमिका तथा विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी के महत्व पर विशेष बल दिया। साथ ही आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रभक्ति के इस महाव्रत में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाने तथा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाले

हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देश के अनुसूचे नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का एक प्रभावी मंच बन गया है। किसी दूरस्थ गांव के शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान, युवा या सामाजिक संगठन द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का प्रधानमंत्री ने उल्लेख करते हैं। इससे ऐसे प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिलती है और देशभर के लोगों को समाजहित में आगे बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संवाद प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकार और जनसेवा की भावना को मजबूत करता है। मन की बात के माध्यम से देश के कोने-कोने में हो रहे सकारात्मक

कार्यों को राष्ट्रीय मंच मिलता है, जिससे विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में जनभागीदारी और अधिक मजबूत होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर कैप कार्यालय में भी मन की बात कार्यक्रम में पहुंचकर आमजन से संवाद किया और कलकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौता और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश जल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। वहीं, राजस्थान पिछले तीन महीनों से अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रहा है।

मन की बात में बार-बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित दया भवन में युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 136वीं कड़ी का श्रवण किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के साथ संवाद का एक ऐसा सशक्त मंच बन गया है, जो समाज के बीच हो रहे

सकारात्मक और प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। देशभर के लोगों को प्रत्येक माह इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा रहती है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, नवाचारों और जन-अभियानों को सामने लाते हैं, जो बिना किसी प्रसिद्धि या व्यक्तिगत अपेक्षा के समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नवाचारों को लगातार मिल रही राष्ट्रीय

पहचान: प्रधानमंत्री द्वारा पिछले कुछ महीनों में मन की बात कार्यक्रम में लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और नवाचारों का उल्लेख किया जाना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। इससे पहले मल्हार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक शक्ति, जनजातीय परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान



किया था।

कोरबा के जल संरक्षण प्रयासों की प्रधानमंत्री ने की सराहना: मन

की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के अंतर्गत देशभर में वर्षा जल संचयन, भूजल

पुनर्भरण, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा में जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को उत्साहजनक बताते हुए उनका सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोरबा में वैज्ञानिक पद्धति से जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए भू-स्थानिक मैपिंग, शैलो एंक्विफर मैनेजमेंट, रिचार्ज वेल तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन

प्रयासों का उद्देश्य वर्षा जल को अधिकतम मात्रा में संरक्षित करना, भूजल स्तर में सुधार लाना और क्षेत्र में जल उपलब्धता को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैच द रेन अभियान के माध्यम से बारिश की प्रत्येक बूंद को सहेजने का जो संदेश दिया है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकता है। जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के

सुरक्षित भविष्य का आधार है।

जल संरक्षण को जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाएगी राज्य सरकार: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, तालाबों और अन्य परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण तथा वृक्षारोपण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जल संरक्षण के कार्य केवल सरकारी योजनाओं और विभागीय गतिविधियों तक सीमित न रहे।